

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के पास प्रवेश और निकास स्थान बनाने से आठ किलोमीटर की दूरी होगी कम, मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ना-उतरना होगा आसान; दिल्ली-नोएडा को मिलेगी राहत

केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और नागर विमानन केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह ने नारियल फोड़ कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इस पर प्रवेश और निकास स्थान अप्रैल तक बनकर तैयार होंगे।

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रांतिरिंग रिपब्लिक सोसाइटी के पास प्रवेश और विकास स्थान बनाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली से आने वाले वाहनों के लिए लालकुआं की तरफ विकास स्थान बनाया जा रहा। इसके बनने से आसपास के लोगों को मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने में आसानी होगी। वहीं, लगभग आठ किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और नागर विमानन केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह ने नायरिल फोड कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इस पर प्रवेश और निकास स्थान अप्रैल तक बनकर तैयार होंगे। क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग दिल्ली से मेट्रो आते हुए लाल कुआं पर निकास और मेट्रो से दिल्ली जाते हुए क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के पास निकास और प्रवेश स्थान बनाने को मांग लंबे समय से केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह कर रहे थे। मौजूदा समय में प्रवेश और निकास स्थान नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही थी।



दिल्ली की तरफ से एक्सप्रेस वे पर आने वाले चालकों को इससे बाहर निकालने के लिए डासना आना पड़ रहा है। उनकी सुविधा के लिए अब चिपियायाने के पास निकास स्थान बनाने का काम शुरू हो गया है। मेट्रो की तरफ से आने वाले वाहनों को एक्सप्रेस वे से बाहर निकालने के लिए एबीएस कॉलेज से थोड़ा पहले निकास स्थान मिलेगा। वहीं क्रासिंग रिपब्लिक सोसाइटी को से फ्लाईओवर शुरू होने से पहले एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए प्रवेश स्थान बनाया

जा रहा है। इससे क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी और अन्य जगह रहने वाले लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा।

एनएचएआई के परियोजना अधिकारी अरविन्द कुमार ने बताया की प्रवेश और निकास स्थान बनाने का काम शुरू हो गया है। निर्माण कार्य अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। निर्माण कार्य पर निकास दस करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रवेश और निकास द्वार बनने से एनएच-9 पर रोजाना लगने वाले

जाम से लोगों को राहत मिलेगी। एनएच-9 की लेन पर सुबह और शाम वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम रहता है। इस कारण परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि सड़क जगह यातायात पुलिस को मौं तैनात है। इसके बावजूद जाम से राहत नहीं मिल रही थी। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोग समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे। अब निकास और प्रवेश स्थान बनने से जाम से राहत मिल सकेगी।

“सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा”



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वाहन चालकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से दिनांक-07.01.2024 रविवार को दो-पहिया वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है।

रैली प्रातः-11:00 बजे
पुलिस आयुक्त कार्यालय से
प्रारम्भ होकर शहर के निम्न मार्गों
से गुजरेगी, रैली का शुभारंभ श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र पुलिस

आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल
द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया
जावेगा ।

रैली मार्ग:- कमिश्नर कार्यालय से रैली टाकीज, टाकीज मंदिर तलैया, भारत टाकीज, अस्पना तिराहा, बस स्टेण्ड, भोपाल टाकीज चैराहा, थाना शाहजहानाबाद, तीन मोहरा, रॉयल मार्केट, जीएडी क्रांतिग, लालघाटी से खान्नागवा, करबला, रेतघाट, पॉलिटेक्निक चैराहा, रोशनपुरा चैराहा, रंगमहल चैराहा, जवाहर चैक, डिपो चैराहा, पीएण्डटी चैराहा, माता मंदिर चैराहा. अर्जुन

नगर, सुभाष स्कुल, राजीव गांधी
चैराहा, प्रशासन अकादमी से
1100 क्वाटर, 10 नंबर
ओल्डकेम्पियन से सात नम्बर,
नरन कॉलेज, व्यापन चैराहा से
जेल रोड होते हुए वापस
कमिश्नर कार्यालय।
आम जनता से अनुरोध है कि
यातायात नियमों का
पालन, यातायात व्यवस्था में
सहयोग करें। किसी प्रकार की
असुविधा होने पर यातायात
दूरभाष नं. 0755-2677340,
2443850 पर सम्पर्क करें।

नगरीय यातायात पुलिस
भोपाल

परिवहन विशेष न्यूज

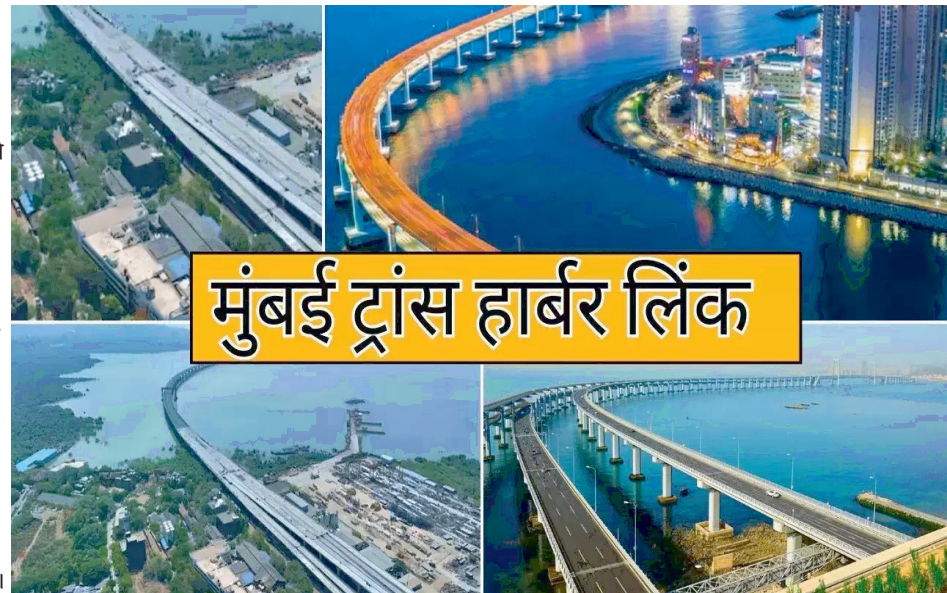
नई दिल्ली। भारत में नए इन्फ्रस्ट्रक्चर का निर्माण लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है। तेज गति से भाग रहे लोगों को अक्सर सबसे अधिक परेशानी जाम को लेकर झेलनी पड़ती है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए नए-नए पुल, हावर्डे और अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। विकास को तेज गति देने के लिए और कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए देश के सबसे बड़े समुद्र पुल का निर्माण किया गया है। इस समुद्री पुल के शुरू होने के बाद जो सफर तय करने में 2 घंटे का समय लगता था उसे अब मात्र 35 मिनट का समय लगेगा। आपकी जानकारी हेतु बता दिये कि यह पुल मुंबई में बनाया जा रहा है और वहां दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई के साथ जोड़ते हुए बाहरी इलाकों तक जाएगा। इस पुल का नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। इस पुल पर वाहनों की 100 की संख्या में ट्रैफिक को रफ्तार से दौड़ाने की इजाजत होगी। इससे रास्तों पर लगने वाला जाम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए लोग इस ब्रिज का उपयोग कर पाएंगे। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।

अब आपको इस पुल और उसके उद्घाटन की तिथि के बारे में जानकारी देते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बनने के बाद यह देश का सबसे बड़ा समुद्र पुल कहा जाएगा। इससे पहले देश का

सबसे बड़ा समुद्र पुल भी मुंबई के वर्ली से बांद्रा के बीच बनाया गया था। नए पुल से पहले मुंबई वर्ली-बांद्रा पुल ही देश का सबसे लंबा समुद्र पुल था। बता दें मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की लंबाई पुराने पुल की तुलना से 4 गुना अधिक है।

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक
21.8 किलोमीटर लंबा
है। इस पुल पर करीब
16.5 किलोमीटर का
सफर समुद्र के ऊपर तय
किया जाएगा। अनुमानित
तौर पर बात करें तो इस
पुल से प्रतिदिन 70 हजार
तक वाहन गुजर सकते हैं।
इस पुल को बनाने में कुल
लागत 17,843 करोड़ रु

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि को आयोजित कार्यक्रम में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक द्वारा समुद्र पुल का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से लंबे समय से समुद्र पुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित किया जाएगा।



मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इस पुल पर कोई रेड लाइट नहीं है। एक बार इस पर चढ़ने के बाद आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा बिना हॉर्न के पार कर सकते हैं। इससे 2 घंटे में तय होने वाला आपका सफर मात्र 35 मिनट में पूरा हो जाएगा। बता दें कि देशीया मुंबई से सर्व मुंबई तक जाने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है, लेकिन इस पुल के बाद यह समय

घटकर 35 मिनट का हो जाएगा। इसके अलावा इस पुल के माध्यम से एयरपोर्ट और पुणे जाने वाले लोगों को भी लाभ होगा। इस पुल का उपयोग कर लोग ना केवल दक्षिण मुंबई से नवी बल्कि पुल का उपयोग कर मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे भी सीधा जा सकते हैं। इस प्रकार से यह नया देश का सबसे लंबा समुद्र पुल लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा।

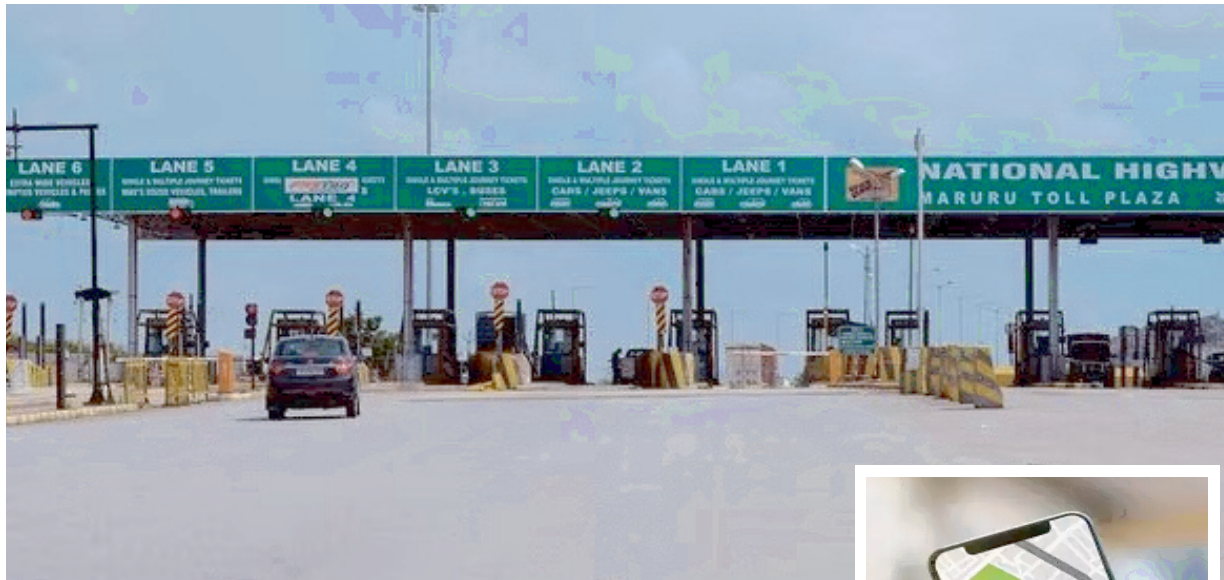
एनएच पर शुरू होगी जीपीएस टोल तकनीक जितनी दूरी उतने का ही टैक्स

परिवहन विशेष न्यूज

एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वालों के लिए एक तरह से अच्छी खबर है. टोल प्लाजा खत्म कर जीपीएस तकनीक से टोल टैक्स जुटाने की तैयारी में सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है.

दिल्ली-जयपुर हाईवे और बंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेससँ पहले दो ऐसे रास्तामार्ग होंगे, जहाँ जीपीएस-आधारित टोलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी ताकि यात्रियों को यात्रा की गई किलोमीटर की संख्या के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना सुनिश्चित हो सके. जीपीएस टोल सिस्टम लागू होने के बाद हाईवे पर टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे और इस सिस्टम से यात्रियों को उतने के ही पैसے देने होंगे, जितनी दूरी वे हाईवे पर तय करके.

जीपीएस टोल प्रणाली की तैयारी का काम शुरू हो गया है और यात्रा के लिए तय की गई दूरी और यात्रा के लिए लगने वाले टोल टैक्स की सटीक गणना के लिए दिल्ली-जयपुर खंड की बेहतरीन जियोफेंसिंग शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि अब टोल टैक्स का कलेक्शन जीपीएस के माध्यम से होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली-जयपुर और बेंगलुरु-मैसूर हाईवे पर हो रही है। मौजूदा समय में 18 लाख से अधिक कर्मशिल वाहनों में जीपीएस-आधारित व्हाइल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लग चुके हैं और शुभआत के तौर पर यह वाहन इसी नई तकनीक से यूजर फ्रीस का भुगतान करना शुरू कर सकते हैं।



नए जीपीएस-आधारित टोलिंग सिस्टम को विभिन्न हिस्सों यानी राजमार्गों पर आजमाया जाएगा और धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में संसद को सूचित किया कि पुनः टोलने के कोटो टोल प्लाजा से मुक्त करने की नई प्रणाली मार्च तक शुरू हो जाएगी. संसद में नितिन गडकरी ने कहा था, 'अब मैं एक जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूँ, जिसमें टोल नहीं रहेंगे पर इसका अर्थ यह नहीं है कि टोल खत्म. मैं सिस्टम में वाहन जो भी जीपीएस सिस्टम ऑनियानिं भी कर दिया गया है. जीपीएस पर

रिपोर्टों होगा कि आपने कहाँ से एंट्री ली और कहाँ निकले और उसी आधार से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और रास्ते में कोई आपको कहीं नहीं रोकेगा, केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन ने कहा कि वे इसे लाजवाब करने की योजना पर काम कर रहे हैं साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट से संबंधी चिंताओं सहित सभी मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है. राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख लक्ष्यों पर अनुराग जैन ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे संबरत और दिल्ली-सूरत हिस्सा पर जीपीएस सिस्टम और अप्रैल तक पूरा हो जाएगा.



इनसाइड



फीमेल ऑर्गेज्म से जुड़े हैं ये 5 अज्ञात फैक्ट्स, जानकर आप भी हो जाएंगी हैरान

महिलाओं के शरीर से जुड़े फैक्ट्स महिलाओं को खुद पता नहीं होते हैं. उन्हें अपने शरीर के बारे में समझने की जरूरत है, खुलकर बात करने की जरूरत है, न की इस पर चुप रहने की. सेक्स जरूरी है और इससे जुड़े अंग जो आपको उत्तेजित करते हैं उसके बारे में जानना भी जरूरी है. आज हम 5 ऐसे ही अज्ञात तथ्यों के बारे में बताते जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होने वाली है. महिलाओं में 3 से अधिक यौन अंग होते हैं ! महिला के बाहरी यौन अंग को लेबिया मेजोरा कहा जाता है. यह योनि के खुलने के आसपास वाली त्वचा होती है, जो 2 फोल्ड्स में मौजूद होती है. भीतरी यौन अंग को लेबिया माइनोरा कहा जाता है, जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होते हैं. आंतरिक महिला यौन अंग में अंडाशय (Ovaries), फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय (Uterus), गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) और योनि (Vagina) हैं. महिला सेक्स सिर्फ प्रजनन (Reproductive) अंग नहीं हैं, वे महिलाओं में यौन उत्तेजना का भी काम करते हैं.

विभिन्न चरणों में समझे फीमेल ऑर्गेज्म जिस तरह से एक महिला को ऑर्गेज्म प्राप्त होता है वह पुरुषों की तुलना में अलग होता है. पहले एक उत्तेजना चरण होता है जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होता है. दूसरा जब क्लाइटोरिस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है. क्लाइटोरिस को "फीमेल पेनिस" भी कहते हैं, जो महिलाओं के शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना गया है. तीसरा चरण ऑर्गेज्म से ठीक पहले होता है जहां हृदय गति सबसे अधिक होती है. अंतिम चरण रिलीज या संभोग का चरण है.

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 8,000 से अधिक तंत्रिका हैं. इस प्रकार से यह सबसे अधिक उत्तेजना उत्प्रेरण अंगों में से एक है. ऐसा कहा जाता है कि 75 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में क्लाइटोरिस को छूने पर ही ऑर्गेज्म चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है. तीन-चौथाई क्लाइटोरिस छिपे हुए होते हैं शायद इसीलिए इसे कामोत्तेजना वाले अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है. क्लाइटोरिस का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आनंद देना होता है.

फीमेल ऑर्गेज्म में स्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

महिलाओं में स्तन और निप्पल की उत्तेजना के कारण भी ऑर्गेज्म प्राप्त किया जा सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि निप्पल को उत्तेजित करने से भी जेनाइटल्स यानी जननांगों को सक्रिय किया जा सकता है.

महिला को आनंद देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं

महिलाओं को सुख देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक अंग से प्रत्येक अंग उत्तेजित होता है. जिस वजह से महिलाओं को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है. पार्टनर की प्राथमिकता, पसंद और सेक्सुअल एनार्टोमी को ध्यान में रखें. इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है.

महिलाओं में होने वाली हेल्थ से जुड़ी परेशानियां, जिनके बारे में जानना है बेहद जरूरी

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना अधिक रहती है लेकिन समय पर इलाज होने पर उपचार संभव है. जानिए महिलाओं में होने वाली कुछ सामान्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में. क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक डेव्स की संभावना अधिक होती है. यही नहीं, डिप्रेशन और एंजायटी की समस्या भी महिलाओं में अधिक देखी जाती है. महिलाओं और पुरुषों दोनों कई हेल्थ कंडिशंस से गुजरते हैं लेकिन कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, जो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं. वहीं जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण कई महिलाओं की हेल्थ कंडिशंस का समय पर निदान नहीं हो पाता.

छात्राओं का बढ़ता यौन उत्पीड़न रोके

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें। क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी व कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत् की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए

डा. वरिंदर भाटिया

देश के अनेक राज्यों के शिक्षा संस्थानों में छात्राओं का यौन शोषण चिंताजनक बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी क्रदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इसके तहत दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। आयोग ने कहा है कि हाल के सालों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है। आयोग कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंतित है। आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के मामले निम्नोबरी और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत हों और केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की गई हो। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) विधेयक 2012 (संशोधित विधेयक) संसद द्वारा 2013 में पारित किया गया था। यौन उत्पीड़न कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। हमारी जानकारी के लिए, किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी लालच देकर अनावश्यक रूप से दबाव बनाना भी यौन शोषण अपराध का हिस्सा होता है। कार्यस्थल पर अश्लील चित्र दिखाना, शरीर के यौन अंग पर टिप्पणी करना, यौन गतिविधियों की अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी महिला के साथ अभद्रता या गाली गलौज करना भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। शिक्षा के मंदिर इसका अपवाद नहीं हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्टिंग की जरूरत होती है परन्तु छात्राओं द्वारा



किन्हीं कारणों से इसको न बताने पर उनका शोषण बढ़ता जाता है। बेहतर है सरकारें छात्राओं से मिली इस जानकारी को गुप्त रख छद्म जांच करें और कार्रवाई करें। कुछ समय से देश के अनेक राज्यों में छात्राओं के यौन शोषण की घटनाओं में बढ़ोतरी से सामाजिक व्याकुलता बढ़ रही है। यौन शोषण का छात्राओं के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जिस मनुष्य का यौन शोषण हुआ होता है वह पूरी मानवता से नफरत करने लगता है। उसे हर व्यक्ति केवल शोषण करने वाला ही दिखता है क्योंकि यह उसकी मानसिकता बन जाती है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है और उसके लिए बहुत सी तकलीफों का सामना भी करना होता है, जैसे कि वह यौन शोषण उसे बार-बार याद आते रहते हैं और उसको और ज्यादा मानसिक तकलीफ होती है जो उसके लिए बहुत कष्टदायक होती है, यह जिस तन लागे वोही जाने वाली स्थिति होती है। आज सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कुछ समय पहले एक छात्र ऑडिट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 24 कॉलेजों और विभागों में सर्वेक्षण किया गया। कुल 810 छात्र-छात्राओं ने सवालों के जवाब दिए। इसमें करीब 90 प्रतिशत महिलाएं और 10 प्रतिशत पुरुष थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हर चार छात्राओं में से एक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। यौन उत्पीड़न के 188 मामलों में 40 मामले शारीरिक उत्पीड़न के थे। उत्पीड़न के पांच में से एक मामला जबरदस्ती छूने या पकड़ने का था। उत्पीड़न के प्रत्येक पांच मामलों में से एक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने या कॉल या लिखित

वॉट्सएप मैसेजों के जरिए उत्पीड़न का था। जवाब देने वाले तकरीबन 80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने परिसर में असुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन की ओर से कदम नहीं उठाने को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा ऑडिट सरकारों की तरफ से सभी कॉलेजों में करवाया जाना चाहिए। सच बोले तो सिर्फ छात्राएं ही नहीं, अमूमन सभी लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है। उन्हें हर कदम पर न जाने कितनी गंदी नजरों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उन्हें खुद को सुरक्षित रखने की चिंता लगी रहती है। ऑफिस या स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, अब तो लड़कियां घर तक पर सेफ नहीं हैं। आए दिन पिता या भाई द्वारा भी रेप की खबरों से सोशल मीडिया भरा रहता है। ऐसे माहौल में आप भी समझ सकते हैं कि यौन उत्पीड़न की वजह से लड़कियों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी लड़कियों को यहां तक कि तदर्थ महिला अध्यापकों को भी पक्की जाँब के लिए यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं जो बेडरूम सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। यह एक न हजम होने वाली सच्चाई हो सकती है। छात्राओं के यौन शोषण को लेकर विदेशी की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आता है लेकिन पिछले कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहां पर छात्राओं का यौन उत्पीड़न सबसे ज्यादा होता है। कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों का यौन उत्पीड़न किया जाना ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में

महामारी के स्तर तक पहुंच चुका है। वहां की कई यूनिवर्सिटियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कर्मचारियों को विद्यार्थियों पर यौन संबंध के लिए दबाव बनाने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी पर्याप्त नियम नहीं हैं। बस इसी बात से आप जान सकते हैं कि जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में लड़कियां और स्टूडेंट्स का ये हाल है तो फिर बाकी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा। एक ज़माने में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को विद्या का मंदिर समझा जाता था और आज अपने देश में भी इनमें से कुछ की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो गई है कि अब इन्हें विद्या का मंदिर नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकारें ऐसे इंतजाम करें, ऐसे रिपोर्टिंग सिस्टम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कहें जिससे छात्राओं के यौन शोषण के मामले दबे नहीं। छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें, क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत् की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि छात्राओं की पढ़ाई-लिखाई को उत्साह देने के लिए उन्हें सुरक्षित अकादमिक माहौल दिया जा सके। छात्राओं के हॉस्टल उनके लिए कितने सुरक्षित हैं, यह वैरिफिकेशन जरूरी और तुरंत हो तो बेहतर है। छात्राओं को सुरक्षित करना ही होगा।

मां बनने के बाद छोटी-छोटी बातें भूलने लगी हैं, तो 'माँमी ब्रेन' प्रॉब्लम से ऐसे करें बचाव



क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मां बनने के बाद छोटी छोटी बातें भूलने लगीं हैं? कभी ऐसा हुआ हो कि आप कमरे में तेजी से गईं और वहां जाकर भूल गई कि आप व यों कमरे में आई या गाड़ी की चाबी हाथ में हैं और आप पूरे फ्लैट में चाबी ढूँढती रहीं? अगर आप ऐसी समस् याओं से परेशान हो गई हैं तो यह अकेले आपकी ऐसी समस् या नहीं है. दरअसल इस समस् या को माँमी ब्रेन के नाम से जाना जाता है. वेरीवेलफैमिली के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जन् म देने से मां का मस्तिष्क भी काफी प्रभावित होता है और कभी-कभी लंबे समय तक इसका असर कायम रहता है. ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने भी ये पाया गया है कि मां बनने से महिला के शब्दाश् त क्षमता पर स थाई असर पड़ता है.

क्या है इस परेशानी की वजह?

कई शोधकर्ताओं ने माना कि ये परिवर्तन एक नई मां को अपने बच्चे की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है. यह भी कहा जा सकता है कि मस्तिष्क में ये परिवर्तन दरअसल नई माताओं को बच्चे की जरूरतों को अपनाने और उन हें पूरा करने के लिए अहम होता है.

माँमी ब्रेन से उबरने के उपाय

धैर्य रखें- शरीर में हुए इस बायोलॉजिकल बदलाव की वजह से आप खुद से परेशान हैं और इर्रिटेट हो जाती हैं आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा एक् स ट ट्रा प्तान बनाएं तो माँमी ब्रेन की समस् या से उबर सकती हैं.

लिस्ट बनाएं- इस समस् या से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने हर काम की लिस्ट बनाएं. इसके लिए आप एक नोटबुक कैरी करें और जब भी कुछ याद आए तो उसे लिख लें. ऐसा करने से आप जरूरी चीजों को भूलेंगी नहीं.

प्लान बनाएं- आप पहले से चीजों के लिए प्लान बनाएं और अपनी हर चीज को सही जगह पर रखने की आदत डाल लें. इससे आपका काम काफी आसान बन जाएगा. मसलन, आप अगर सुबह डॉक्टर के पास जाने वाली हैं तो रात में ही सारा सामान तैयार रखें. आप चाभी, वॉलेट आदि हमेशा एक ही जगह पर रखें आदि.

पर्याप्त नींद जरूरी- नई मांओं की एक् स ट तता 24 घंटे की होती है. लेकिन आपको कुछ इस तरह अपने रुटीन को फॉलो करना है कि आपकी नींद पूरी हो सके. इसके लिए आप परिवार के लोगों की मदद ले सकती हैं और बच्चे के साथ ही सोने और जागने की रुटीन को फॉलो कर सकती हैं. भरपूर नींद आपके ब्रेन को रिलैक् स करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर पाएगा.

ब्रेन को दें एक्स्ट्रा केयर- ब्रेन के लिए आप अपने खानपान पर ध्यान दें और ब्रेन गेम खेलें. ब्रेन गेम आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. इसके अलावा, आप उन चीजों को डाइट में शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और भरपूर प्रोटीन हो.

बच्चा होने के बाद महिलाएं इस परेशानी का हो सकती हैं शिकार, वक्त रहते कर लें उपाय, वरना बिगड़ जाएगी कंडीशन....

पोस्टपार्टम डिप्रेशन की समस्या इन दिनों कॉमन होती जा रही है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन की समस्या इन दिनों कॉमन होती जा रही है.

पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है, जो तमाम महिलाओं को बच्चे को जन्म देने के बाद हो जाती है. इस कंडीशन से करीब 15 प्रतिशत महिलाएं प्रभावित होती हैं. पोस्टपार्टम डिप्रेशन के दौरान महिलाएं बार-बार रोने लगती हैं और उन्हें अत्यधिक तनाव हो जाता है. इससे छुटकारा पाना बेहद जरूरी है.

महिलाओं के लिए मां बनना एक सुखद अहसास होता है. प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें कई उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ता है और तब जाकर उन्हें संतान सुख मिल पाता है. हालांकि बच्चा होने के बाद भी बड़ी संख्या में महिलाएं परेशान हो जाती हैं और कई तरह की समस्याओं का शिकार हो जाती हैं. इसमें से एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जिसे PPD भी कहा जाता है. करीब 15 प्रतिशत महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद इस समस्या का शिकार हो जाती हैं और उनकी फिजिकल व मेंटल हेल्थ बुरी तरह प्रभावित होती है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने पर महिलाएं इमोशनल हो जाती हैं और बार-बार रोने लगती हैं. उन्हें हर वक्त थकान महसूस होती है और बिना किसी बात के टेशन होती रहती है. इसकी वजह से बच्चे की देखभाल सही



तरीके से नहीं कर पाती हैं.

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. बंदना सोढ़ी कहती हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक कॉमन मूड डिसऑर्डर है, जो बच्चे को जन्म देने के बाद करीब 15 प्रतिशत महिलाओं को प्रभावित करता है. इसकी वजह से महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को हॉर्मोनल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल

महिला बच्चे को जन्म देने के बाद दुखी, निराश महसूस कर रही है या खुद को दोषी समझ रही है, तो यह इस समस्या का लक्षण है. अत्यधिक चिंता करना या घबराहट महसूस होना, अपनी पसंदीदा चीजों में इंटरैस्ट खत्म होना, खाना न खाना, हमेशा थका हुआ महसूस करना, नींद आने में परेशानी होना या बिना किसी वजह से रोना, सुसाइड करने का खयाल आना या बच्चे को लेकर अत्यधिक चिंतित महसूस करना पोस्टपार्टम डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण हैं.

क्या है इस परेशान का इलाज और बचाव

एक्सपर्ट की मानें तो सभी महिलाओं की कंडीशन के अनुसार पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज किया जाता है. कई महिलाओं को एंटी डिप्रेशन दवाएं दी जाती हैं, जबकि कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए रिकवर होने में मदद की जाती है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन के गंभीर मामले रेयर ही होते हैं और डॉक्टर की मदद लेकर इससे रिकवर होना आसान है. इससे बचने के लिए हेल्दी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, बाहर घूमना और लोगों से बातचीत करना, सेल्फ केयर, घरेलू कामकाज और अपनी पसंद की एक्टिविटी करनी चाहिए. अगर आप इसे लेकर पहले से ही सावधान रहेंगे, तो बचाव किया जा सकता है।

स्क्रेप माफियाओं का नेक्सस टूटा, जाने बदमाशी के दम पर कैसे चलता है धंधा!

परिवहन विशेष न्यूज़

नई दिल्ली। जिला गौतमबुद्ध नगर में संगठित अपराध पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का लगातार वार जारी है। हालांकि संगठित अपराध पर लगाम कसने की शुरुआत तत्कालीन जिलाधिकारी बीएन सिंह ने की। जिन्होंने अलग-अलग गैंग को सूचीबद्ध कर उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। जितने लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया था उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि कोर्ट ने जिलाधिकारी के फैसले को सही माना। इसी कड़ी में जब गौतमबुद्ध नगर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू हुई तो गैंगस्टर में निरोध करने की शक्ति पुलिस कमिश्नर के हाथ में आ गई। गौतम बुद्ध नगर के पहले कमिश्नर आलोक सिंह के समय उन लोगों पर कार्रवाई हुई। जिन पर गैंगस्टर लग चुका था और उनकी संपत्ति भी मुकदमों में अटक कर दी गई थी।

पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के साथ-साथ स्क्रेप ठेकेदार निजाम मलिक उर्फ मुनीम पर शिकंजा कसा। इसी सब के बीच रवि काना एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया, जिसने स्क्रेप ठेकेदारों को घर बैठा दिया। कथित तौर पर सुंदर भाटी से साठगांठ होने के चलते निजाम मलिक नोएडा ग्रेटर नोएडा की कई बड़ी फैक्ट्री में अपनी धाक जमा कर स्क्रेप के ठेके लेता था। मगर रवि काना ने पुलिस



अधिकारियों के साथ मिलकर सुंदर भाटी, निजाम मलिक व अन्य स्क्रेप ठेकेदारों को ठिकाने लगाने की शुरुआत की। सबसे पहले थाना बीटा-2 में निजाम मलिक व उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। गैंगस्टर में कार्रवाई भी हुई। उनकी कई सौ करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली। जानकारी बताते हैं की संपत्ति पुलिस ने

जब्त कर ली। यह सब कार्यवाही रवि काना के साथ पुलिस के घट जोड़ का नतीजा था। जो उसने पुलिस अफसर से किया था। ऐसा भी बताया जाता है कि उसने कई भाजपा के बड़े नेताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया था। कोई भी स्क्रेप ठेकेदार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यदि बिना रवि काना की अनुमति के ठेका लेता

तो उसके माल को गाड़ी समेत फैक्ट्री से निकलते ही हाईजैक कर लिया जाता था। गत्ता व्यापारी ने भी इसी तरह का एक मुकदमा दर्ज कराया था।

कैसे चलता आ रहा था स्क्रेप का कारोबार

गौतमबुद्ध नगर में स्क्रेप की ठेकेदारी वाला काम हमेशा ही विवादों में रहा है

और लगातार स्क्रेप ठेकेदारों का आपस में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है। एक वक्त था जब दादरी के रहने वाले फरमान मलिक की रेलवे फाटक के पास हत्या की गई। उसे दौरान चर्चा थी कि स्क्रेप ठेकों को लेकर ही फरमान मलिक की हत्या की गई है। इस हत्याकांड में निजाम मलिक उर्फ मुनीम और उनके बेटों खिलाफ थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज की गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। स्क्रेप ठेकों को लेकर हमेशा खींचतान चलती रही। निजाम मलिक ही ज्यादातर बड़ी फैक्ट्री में स्क्रेप के ठेके लेने लगे। उनके अलावा भी कई अन्य लोग इस क्षेत्र में उतरे मगर वह कामयाब नहीं हो पाए। सरिया और स्क्रेप का धंधा रवि काना ने भी शुरू कर दिया, मगर रवि काना की दाल नहीं गल पा रही थी। दरअसल निजाम मलिक की अलग अलग फैक्ट्री में अच्छी पकड़ थी और उन्हीं को एलजी और सैमसंग जैसी कंपनियों से स्क्रेप का ठेका मिलता था। वक्त बिता गया और रवि काना ने इस तरह की साठगांठ बिठाई कि निजाम मलिक को ही ठिकाने लगा दिया। उनके खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हुए और उनकी संपत्ति तक अटक हो गई। अब रवि काना की भी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जल्दी रवि काना कोर्ट में खुद को सरेंडर कर देगा।

पुलिस के मुताबिक, रवि काना का असली नाम रवींद्र नागर है. वह 16 सदस्यीय गिरोह चलाता है.

परिवहन विशेष न्यूज़

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के बड़े स्क्रेप माफिया से करोड़पति बनने वाले रवि काना और उसकी गलफ़ेंड की अब तक 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस सील कर चुकी है. दिल्ली के न्यू फ़ेंडस कॉलोनी में एक आलीशान कोठी रवि काना की 'गलफ़ेंड' काजल झा की भी है।

काजल की 100 करोड़ की कोठी पुलिस ने सील कर दी। आपको बता दें कि रवि काना की गलफ़ेंड काजल झा नैकरी की तलाश में उसके साथ संपर्क में आई थी और उसके गिरोह का हिस्सा बन गई. इतना ही नहीं वह गैंग की सबसे अहम सदस्य बन गई. काजल झा रवि काना की सभी बेनामी संपत्तियों का हिस्सा-

किताब संभालती थी और रवि काना ने उसे साउथ दिल्ली की पॉश न्यू फ़ेंडस कॉलोनी में करोड़ 100 करोड़ का तीन मंजिला बंगला गिफ्ट किया. पुलिस ने बुधवार को उसकी प्रॉपर्टी पर छापेमारी की, इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए काजल झा और उसके सहयोगी वहां से भाग गए. हालांकि पुलिस ने बाद में बंगले को सील कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, रवि काना का असली नाम रवींद्र नागर है. वह 16 सदस्यीय गिरोह चलाता है. वह सरिया और कबाड़ की अवैध खरीद और बिक्री करता है. स्क्रेप डीलर के तौर पर रवि काना ने कथित तौर पर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में व्यवसायियों से जबरन वसूली और कबाड़ के सामान को अवैध रूप

से हासिल किया. इसे बेचने के लिए एक गिरोह बनाया और करोड़पति बन बैठा. रवि काना ग्रेटर नोएडा के गैंगस्टर हरेंद्र प्रधान का भाई है और हरेंद्र प्रधान को साल 2014 में उसके एक विरोधी गिरोह ने मार दिया था. उसकी मौत के बाद रवि काना ने गिरोह की बागडोर संभाल ली. ग्रेटर नोएडा के सीनियर पुलिस अधिकारी साद मिया खान ने बताया कि गैंगस्टर और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपहरण और चोरी के आरोप समेत अब तक 11 मामले दर्ज किए गए हैं. गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा में गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई स्क्रेप गोदामों पर छापा मारकर उनको सील कर दिया गया है।



मोदी मिल फ्लाईओवर के नीचे लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची; मथुरा रोड पर लगा लंबा जाम

दक्षिणी दिल्ली के मोदी मिल फ्लाईओवर के नीचे शनिवार शाम को डीपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। इससे आसपास के इलाके में धुंआ ही धुंआ फैल गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। इससे आश्रम से फरीदाबाद जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया। लोगों को इससे काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

दिल्ली। मोदी मिल फ्लाईओवर के नीचे शनिवार शाम को डीपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। इससे आसपास के इलाके में धुंआ ही धुंआ फैल गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। इससे आश्रम से फरीदाबाद जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि आग लगने की वजह से आश्रम से अपोलो अस्पताल जानेवाले मथुरा रोड पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक, लकड़ियों और पेड़ की पत्तियों का कूड़ा होने से आग और धुंआ तेजी से फैल गया। दमकल कर्मियों ने पानी की बोखारों से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह डीपिंग ग्राउंड पीडब्ल्यूडी का है। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है।



बढ़ेंगी बृजभूषण सिंह की मुश्किलें, पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से की यह मांग

महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से भाजपा सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह किया है। पुलिस ने अभियुक्तों की इस दलील का विरोध किया कि चूंकि कुछ घटनाएं विदेशों में हुईं, इसलिए वह दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से भाजपा सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह

किया है। पुलिस ने अभियुक्तों की इस दलील का विरोध किया कि चूंकि कुछ घटनाएं विदेशों में हुईं, इसलिए वह दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुत किया कि सिंह द्वारा विदेशों और दिल्ली सहित भारत के अन्य राज्यों के अंदर की गई यौन उत्पीड़न की घटनाएं उसी अपराध का हिस्सा हैं। पुलिस ने न्यायाधीश से कहा इस मामले की सुनवाई का अधिकार दिल्ली की अदालत का है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की है।



संजय सिंह फिलहाल दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

संजय सिंह को कोर्ट से मिली एक और बड़ी राहत, राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक और बड़ी राहत दी है। उन्हें नामांकन करने के लिए शारीरिक रूप जाकर से फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। संजय सिंह फिलहाल दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक और बड़ी

राहत दी है। उन्हें नामांकन करने के लिए शारीरिक रूप जाकर से फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। संजय सिंह फिलहाल दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि संजय सिंह को 8 जनवरी के साथ-साथ 10 जनवरी को रिवर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में ले जाया जाए, ताकि वो राज्यसभा चुनाव के संबंध में अपना नामांकन पत्र जमा कर सकें और जांच भी कर सकें।

अदालत ने कहा, ६ अभियुक्त संजय सिंह को नामांकन और दस्तावेजों की जांच की उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने तक वहां रहने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि जेल से बाहर आकर नामांकन करने से जेल लौटने तक संजय सिंह मोबाइल फोन

का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस मामले में और सीबीआई से जुड़े मामले के किसी अन्य आरोपी, संदिग्ध और गवाह से बात करने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया से बात करने या प्रेसवार्ता करने के साथ ही कोई बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, उन्हें अपने नामांकन और जांच प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वकील के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

शुक्रवार (5 जनवरी) को कोर्ट ने दी नामांकन की अनुमति राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने संजय सिंह के आवेदन पर सुनवाई के बाद उन्हें नामांकन जेल से नामांकन फार्म भरने की अनुमति दे दी थी।



विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि संजय सिंह को 8 जनवरी के साथ-साथ 10 जनवरी को रिवर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में ले जाया जाए, ताकि वो राज्यसभा चुनाव के संबंध में अपना नामांकन पत्र जमा कर सकें और जांच भी कर सकें।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जारी किया लोगो



परिवहन विशेष।एसडी सेठी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद थीम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। शनिवार को पार्टी अध्यक्ष खड्गे और राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो भी जारी कर दिया है। अबकी बार ये यात्रा हाईब्रिड मोड में होगी जिसमें सभी तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा। तीन राज्यों में करारी हार झेलने के बाद, राहुल गांधी को उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान वह कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने में कामयाब होंगे। शुरुवात में मणिपुर से आगाज करने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, असम से होकर निकलेगी। यात्रा का 2.0 के तहत बेरोजगारी, और महंगाई पर फोकस रहेगी।

स्वाति मालीवाल का इस्तीफा एलजी सक्सेना के पास भेजा गया, 8 जनवरी को करेंगी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) की उम्मीदवार स्वाति मालीवाल का दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उपराज्यपाल को भेज दिया है। सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मालीवाल सोमवार को यहां राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। 19 जनवरी को संभवतः चुनाव होना है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) की उम्मीदवार स्वाति मालीवाल का दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उपराज्यपाल को भेज दिया है। सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मालीवाल सोमवार को यहां राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आप ने शुक्रवार को दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख मालवाल को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया और साथ ही पार्टी ने मौजूदा राज्यसभा सदस्यों संजय सिंह तथा नारायण दास गुप्ता को इस बार फिर उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली की तीन राज्यसभा सीट से संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास गुप्ता का मौजूदा कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म होगा।

सुशील गुप्ता की जगह स्वाति बर्नी प्रत्याशी

मालीवाल को सुशील कुमार गुप्ता की जगह उम्मीदवार बनाया गया है, जो आम आदमी पार्टी (AAP) की हरियाणा इकाई के प्रमुख हैं। पार्टी के अनुसार, सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा की चुनावी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा जताई है। यदि आवश्यक हुआ तो राज्यसभा चुनाव 19 जनवरी को होगा।



दिल्ली-नोएडा के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर

मेरठ एक्सप्रेस-वे पर आना-जाना होगा आसान; लंबे समय से थी ये डिमांड

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) पर अगले तीन माह में क्रासिंग रिपब्लिक के पास वाहनों के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए प्वाइंट बनकर तैयार जाएंगे। शुक्रवार दोपहर को इसका विधिवत शिलान्यास केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह ने नारियल फोड़कर कर दिया। दो माह पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई थी। सर्वे के बाद डिजायन बनाने में विलंब होने से यह काम देरी से शुरू किया गया है।

गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) पर अगले तीन माह में क्रासिंग रिपब्लिक के पास वाहनों के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए प्वाइंट बनकर तैयार जाएंगे। शुक्रवार दोपहर को इसका विधिवत शिलान्यास केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह ने नारियल फोड़कर कर दिया। दो माह पहले इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई थी। सर्वे के बाद डिजायन बनाने में विलंब होने से यह काम देरी से शुरू किया गया है। दोनों प्वाइंट के बनने से लाखों लोगों को दिल्ली से मेरठ आने-जाने में सहूलियत होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए साढ़े नौ करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। दोनों तरफ वाहनों की निगरानी के लिए आठ सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। एबीईएस और क्रासिंग रिपब्लिक के सामने सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और दिल्ली के कई लाख लोगों को आने-जाने में इन दोनों कट से बहुत ही सुविधा होगी। साथ ही



स्थानीय स्तर के लोगों को चढ़ने और उतरने में भी आसानी होगी। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार सुधार के कार्य चल रहे हैं और भविष्य में भी जारी रहेंगे।

डीएमई और एनएच-9 पर आवागमन होगा आसान

नए प्वाइंट बनने के साथ ही डीएमई और एनएच-9 पर वाहनों का आना-जाना आसान हो जाएगा। हापुड़ की तरफ से एनएच-9 से होकर आने वाले ट्रैफिक को क्रासिंग रिपब्लिक के करीब 300 मीटर आगे दिल्ली की तरफ डीएमई पर नया प्रवेश दिया जाएगा। इससे क्रासिंग रिपब्लिक के

अलावा गाजियाबाद और हापुड़ की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को आसानी से डीएमई पर प्रवेश मिल जाएगा।

जाम से भी मिलेगी मुक्ति

सर्विस रोड को चौड़ा कर मेरठ से आने वाले वाहनों के लिए क्रासिंग रिपब्लिक के सामने

निकास को करीब 500 मीटर पीछे किया जाएगा। इससे डीएमई से ट्रैफिक उतरकर एनएच-9 पर आ जाएगा। क्रासिंग रिपब्लिक की सर्विस रोड से वाहन अंदर जा सकेगे। इससे जाम नहीं लगेगा। साथ ही दिल्ली से आने वाले वाहनों के लिए विजयनगर के पास नया निकास भी मिल जाएगा।

रात में खाना खाकर सोया परिवार सुबह उठा ही नहीं; पड़ोसी ने देखा तो उड़ गए होश

कानवनी में मजदूरी करने वाले मनीष बृहस्पतिवार देर रात को शीतलहर के चलते अंगीठी पर ताप रहे थे। नींद आने पर पूरा परिवार जलती अंगीठी छोड़कर सो गया। सुबह सीमा ने जाकर देखा तो पूरा परिवार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तुरंत एंबुलेंस बुलाकर घायल अवस्था में परिवार के चारों सदस्यों को संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया

गाजियाबाद। अंगीठी जलाकर सोने पर एक ही परिवार के चार लोगों की हालत बिगड़ गई है। कानवानी में मजदूरी करने वाले मनीष बृहस्पतिवार देर रात को शीतलहर के चलते अंगीठी पर ताप रहे थे। नींद आने पर पूरा परिवार जलती अंगीठी छोड़कर सो गया।

पूरा परिवार मिला बेहोश

सुबह सीमा ने जाकर देखा तो पूरा परिवार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तुरंत एंबुलेंस बुलाकर घायल अवस्था में परिवार के चारों सदस्यों को संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डाक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि 45 वर्षीय असमानी की हालत गंभीर है।



सांस लेने में भारी परेशानी

धुआँ के चलते सांस लेने में भारी परेशानी होने लगी। आक्सीजन स्तर गिरने लगा। आक्सीजन देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो बेहतर इलाज के लिए असमानी को जीटीबी दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा मनीष व उसके 11 वर्षीय बेटे कृष्ण और आठ वर्षीय बेटी दीपाली की हालत नियंत्रण में है। तीनों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। चिकित्सक की सलाह है कि शीत लहर से बचाव के लिए अलाव खुले स्थान में जलाना चाहिए। घर में जलाए लेकिन सोने से पहले उसे जरूर बुझाना चाहिए। आग जलने से धुआँ बरकार रहता है। इससे सांस लेने में परेशानी होती है। दम घुटने से जान को खतरा रहता है।

इस इलाके में तीन दिन से सप्लाई बाधित, खारा पानी पीने को मजबूर लोग



कोयल एन्क्लेव के -11 के ए बी व सी ब्लॉक में 504 फ्लैट हैं। इनमें से करीब 75 फ्लैट में लोग रह रहे हैं। मंगलवार रात करीब 12 बजे पैनल में फाल्ट होने से तीनों ब्लॉक की आपूर्ति बाधित हो गई थी। लोगों का आरोप है कि जीडीए में लगातार शिकायत करने के बाद भी आपूर्ति अभी तक सामान्य नहीं की गई है।

साहिबाबाद। कोयल एन्क्लेव के -11 सोसाइटी के पैनल में फाल्ट होने से पिछले तीन दिन से विद्युत आपूर्ति बाधित है। पावर बैकअप की सुविधा नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। शाम होते ही सोसाइटी में अंधेरा छा जाता है। आरओ नहीं चलने से लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं।

कोयल एन्क्लेव के -11 के ए, बी व सी ब्लॉक में 504 फ्लैट हैं। इनमें से करीब 75 फ्लैट में लोग रह रहे हैं। मंगलवार रात करीब 12 बजे पैनल में फाल्ट होने से तीनों ब्लॉक की आपूर्ति बाधित हो

गई थी। लोगों का आरोप है कि जीडीए में लगातार शिकायत करने के बाद भी आपूर्ति अभी तक सामान्य नहीं की गई है।

शुक्रवार देर शाम तक केवल बी-ब्लॉक में ही विद्युत आपूर्ति सामान्य हुई है। इससे करीब 15 परिवारों को राहत मिली है। बाकी ए व सी-ब्लॉक के 60 परिवार अभी भी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। सोसायटी के सुनील कुमार ने बताया कि शाम होते ही यहां अंधेरा छा जाता है। इससे लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं।

अधिक टीडीएस का पीना पड़ रहा पानी

लोगों का कहना है कि यहां पर भू-जल की सप्लाई होती है। इस पानी का टीडीएस बहुत अधिक है। इसे कम करने के लिए घरों में आरओ लगाए गए हैं। लेकिन बिजली नहीं होने से आरओ बंद पड़े हुए हैं। इससे लोगों को अधिक टीडीएस का पानी ही पीना पड़ रहा है। कुछ लोग खसैदकर

काम चला रहे हैं।

केवल सार्वजनिक क्षेत्र में है जेनरेटर सेट की सुविधा

सोसायटी के केवल कामन एरिया में जेनरेटर सेट से पावर आपूर्ति की सुविधा है। फ्लैट के लिए जेनरेटर की सुविधा नहीं है। सर्दी में बिजली नहीं होने से लोग पानी गर्म करने, हीटर चलाने समेत विभिन्न कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इससे यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पैनल में समस्या होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। एक ब्लॉक में आपूर्ति सामान्य हो गई है। बाकी दो ब्लॉक में भी जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। विद्युत निगम मेटेनेंस में सहयोग नहीं कर रहा है।

–विनोद कटारिया, सहायक अभियंता, जीडीए जोन-आठ

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में 10 घंटे नहीं आएगी बिजली, विभाग ने लोगों से की सहयोग की अपील

नोएडा व ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सूरजपुर समेत अन्य स्थानों व एनपीसीएल से जुड़े 33 केवी के आठ फीडरों पर आपूर्ति बाधित रहेगी। ऐसे अगर आप इस दिन बिजली से जुड़ कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं तो उस वैकल्पिक व्यवस्था करके रखें।

नोएडा। विद्युत निगम की तरफ से रविवार को 220 केवी मल्टी सर्किट लाइन पर मेघा शटडाउन लिया जाएगा। इसके चलते नोएडा व ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इन इलाकों में बंद रहेगी आपूर्ति

अधिशासी अभियंता विद्युत निगम अभिषेक कुमार ने बताया कि 220 केवी ग्रेटर नोएडा व सेक्टर-20 लाइन और 132 केवी ग्रेटर नोएडा व सूरजपुर डीसी लाइन लाइन पर शटडाउन रहेगा। इसके चलते नोएडा में सेक्टर-50, सेक्टर-64, सेक्टर-52, सेक्टर-60, सेक्टर-56, सेक्टर-67, सेक्टर-72, सेक्टर-63बी, सेक्टर-63 जे समेत अन्य सेक्टरों की आपूर्ति बंद रहेगी।



एलिवेटेड रोड पर शराब पीकर हुड़दंग करना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद तीन गिरफ्तार

गाजियाबाद में दो दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए एलिवेटेड रोड पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाला वीडियो इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र का था। पुलिस ने हुड़दंग करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कार को सीज कर लिया गया है। तीनों आरोपितों की पहचान कानवनी के वेदपाल सौरभ राजपूत और संदीप मालवीय के तौर पर हुई है।

गाजियाबाद। जिले में दो दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए एलिवेटेड रोड पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाला वीडियो इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र का था। पुलिस ने हुड़दंग करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कार को सीज कर लिया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपित कानवनी का वेदपाल, सौरभ राजपूत और संदीप मालवीय हैं। यह सभी एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी करके शराब पी रहे थे। इसके बाद म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। अपने साथ-साथ एलिवेटेड रोड से गुजर रहे लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे थे। पुलिस अन्य आरोपितों को भी तलाश कर रही है।

अशोक सिंघल से मुलाकात, राम भक्त बन कर प्रोजेक्ट पूरा करने की बात, राम मंदिर बनाने वाली कंपनी L&T, जिसने कई चुनौतियों को पार करके देश का मान बढ़ाया

अभिनय आकाश

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने वर्षों पहले निर्माण कंपनी के साथ हुई अशोक सिंघल की बात को आगे बढ़ाते हुए इस बाबत उसी कंपनी बात की और कंपनी इसे स्वीकारते हुए कहा कि हम इसे सेवा भाव से बनाएंगे।

90 के दशक की बात है राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था। मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले वीएचपी के दिगगज नेता अशोक सिंघल ने एक कंपनी के पास जाकर कहा-राम मंदिर तो बनाकर रहेंगे क्या आपका सहयोग मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी बनाए जिसे निर्माण के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव हो। जवाब में कंपनी की तरफ से कहा गया राम का मसला है इसलिए हम ऐसा जरूर करेंगे। इस बात को दशक गुजर गए। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे से पहले मंदिर फिर सरकार के नारे बदलते रहे लेकिन कल कल बहती सरस्वती की धार अपने अराध्य के इंतजार में बैठी रही। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रामलला की जमीन के हक पर हस्तान्तरण के साथ ही ये साफ हो गया कि

अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर जरूर बनेगा। बाद में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। ट्रस्ट के गठन के बाद कई कंपनियों ने मंदिर निर्माण के लिए अपना प्रस्ताव आगे बढ़ाया। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने वर्षों पहले निर्माण कंपनी के साथ हुई अशोक सिंघल की बात को आगे बढ़ाते हुए इस बाबत उसी कंपनी बात की और कंपनी इसे स्वीकारते हुए कहा कि हम इसे सेवा भाव से बनाएंगे।

राम की नागरी अयोध्या पर इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरे ठहरी हुई हैं। राम मंदिर सहित पूरे शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित अभिषेक समारोह 22 जनवरी, 2024 को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या से अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च कर इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। अब खुद उद्घाटन में शिरकत करेंगे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि राम मंदिर बनाने में किस कंपनी का हाथ है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कर रही

है। इस कंपनी का इतिहास शानदार रहा है, जिसने समय-समय पर कई चुनौतियों को पार करके देश का मान बढ़ाया है। 22 जनवरी को इसका पहला फेज कंपनी पूरा कर लेगी। एलएंडटी ने इस मंदिर को इस तरह से तैयार किया है कि अगले 1,000 साल तक इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा।

सरदार सरोवर डैम, रियाद मेट्रो, लोट्स टैपल इस कंपनी ने क्या-क्या बनाया

गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास बनी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और गुजरात के ही मोरेशा में बनी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया की सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें एक साथ 1 लाख 32 हजार लोग एकट्ठ बैठकर क्रिकेट का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब का रियाद मेट्रो और दिल्ली की लोट्स टैपल जैसी खूबसूरत इमारत को बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एल एंड टी) जिसका नाम सुनकर एक बार में आपको लगेगा कि ये कोई विदेशी कंपनी है। लेकिन ऐसा नहीं है एल एंड टी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कर रही



कंपनी है जिसने भारत के विकास के लिए काफी काम किया है।

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक

पहली मेगा प्रोजेक्ट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी एक निर्माणधीन 21.8 किमी लंबा सड़क पुल है जो भारतीय शहर मुंबई को इसके उपग्रह शहर नवी मुंबई से जोड़ता है। इसे एल एंड टी और टाटा तैयार कर रही है। ज्यादातर हिस्सा एल एंड टी द्वारा बनाया जा रहा है। 190 मीटर से 180 मीटर लंबाई के 7 ओएसडी (ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक) स्पैन हैं जिनका उपयोग भारत में पहली बार

पुल पर किया जाता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।

क्या विदेशी है ये कंपनी

साल 1934 की बात है डेनमार्क की एक मशीन बनाने वाली कंपनी ने सिविल कैमिकल इंजीनियर हैनिंग होल्त्व लार्सन को सीमेन्ट बनाने वाली कंपनी के मर्जर के सिलसिले में भारत भेजा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो गया। जिसके बाद ये दोनों वापस

नहीं लौट सके और भारत में ही रहने लगे। मुंबई में एक छोटे से रूम से एच पार्टनरशिप फर्म के रूप में एल एंड टी की शुरुआत की। इसे 1946 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अनिल मणिभाई नाइक ने साल 1965 में एक असिस्टेंट इंजीनियर के रूप एल एंडटी को जॉइन किया था। इसके बाद साल 1999 में वे कंपनी के सीईओ और एमडी बन गए।

अलग-अलग फील्ड में किया काम

टेक्नोलॉजी, डिफेंस और फाइनेंस जैसी फील्ड में भी एल एंड टी काफी तेजी से आगे

बढ़ रही है। आप जानकर हैरान होंगे की देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात हो या फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरिहंत का निर्माण हो सरकार ने एल एंड टी पर ही भरोसा जताया। यहां तक की मंगलयान, चंद्रयान जैसे मिशन भी एल एंड टी के स्पेसर्ट के बिना पूरे नहीं हो पाते।

राम भक्त बन कर पूरा कर रहे प्रोजेक्ट

राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कर रही संस्था लार्सन एंड टुब्रो के चीफ फाइनेंशल अफसर आर शंकर रमन राम मंदिर के निर्माण को महज एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए चैलेंज है। नामी कंपनियों ने मंदिर निर्माण की तकनीक पर शोध किया उसका उपयोग मंदिर निर्माण में हो रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं जो राम मंदिर जैसे महान प्रोजेक्ट के निर्माण की जिम्मेदारी मिली। राम मंदिर के निर्माण में प्राचीन परंपरागत तकनीक के साथ आधुनिक तकनीक का समन्वय किया गया। आर शंकर रमन ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए एक सामान्य प्रोजेक्ट न होकर एक सप्रिचुअल जर्नी है। जिसे हम राम भक्त बन कर संपूर्ण आस्था के साथ पूरा कर रहे हैं।

सिर्फ इतने रुपये की मासिक EMI पर घर आएगी हीरो की ये चर्चित मोटरसाइकिल, देखें क्या है पूरा प्लान

दोपहिया सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर का जलवा पिछले कई सालों से कायम है। अगर आप इस चर्चित बाइक को मासिक किस्तों पर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसे घर लेने के लिए पूरा तरीका बताया गया है। अगर इसके लिए 20 हजार रुपये की डाउनपेमेंट करी जाती है तो बहुत कम रुपये की EMI बनेगी। आइए इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। दोपहिया सेगमेंट में अगर किसी को बजट रेंज के अंदर बाइक खरीदनी होती है, तो उसके जेहन में हीरो स्प्लेंडर का नाम जरूर आता है। इस बाइक ने देश के लोगों के दिलों में अपनी अच्छी पहचान बनाई है। ऐसे में अगर आप भी इस चर्चित मोटरसाइकिल को मासिक EMI पर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हम आपके लिए इसी बाइक का पूरा मासिक ईएमआई प्लान लेकर आए हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक की (Self Alloy) कीमत 90,579 रुपये एक्सशोरूम दिल्ली से शुरू होती है। अगर बाइक के लिए

ग्राहक के द्वारा 20 हजार रुपये की डाउनपेमेंट दी जाती है, तो उसके लिए 70 हजार रुपये का लोन कराया जाएगा।

अगर लोन 36 महीने के लिए कराया जाता है और 10 प्रतिशत की ब्याज दर ली जाती है तो इसके लिए आपको हर महीने 2,548 रुपये देने होंगे।

कुलमिलाकर आपको ब्याज के साथ 1.11 लाख रुपये चुकाने होंगे और बाइक आपकी हो जाएगी। ध्यान रखें ये राशि आपकी डीलरशिप के अनुसार थोड़ी बहुत उपर नीचे भी हो सकती है। खरीदने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें।

माइलेज में है बेस्ट

हीरो की तरफ से आने वाली ये मोटरसाइकिल माइलेज के मामले में बेहद ही शानदार है। इसमें 60 किमी/प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। बाइक में 97.2 सीसी का इंजन प्रदान किया जाता है। जिसको 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसमें 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है। बाइक में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दिया जाता है।



स्पोर्ट्स बाइक शौकीनों के लिए कावासाकी का तोहफा, इन पर मिल रहे हैं शानदार ऑफर्स; जानें डिटेल

कावासाकी ने हाल ही में एलिमिनेटर 500 को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है। वहीं अब कंपनी की तरफ से ग्राहकों के लिए ऑफर्स की घोषणा की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी की बाइक्स पर 60 हजार रुपये तक बचाने का शानदार मौका मिल रहा है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। जापानी वाहन निर्माता कंपनी Kawasaki ने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए कंपनी ने अपनी कई मोटरसाइकिल पर ऑफर देने की घोषणा की है। इसके अलावा वाउचर भी मिल रहे हैं। कुल मिलाकर वर्तमान समय में बाइक खरीदने पर आपकी अच्छी बचत हो सकती है। हम यहां कावासाकी के द्वारा दिए जा रहे ऑफर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

इन पर मिल रहा ऑफर

कावासाकी की तरफ से आने वाली Kawasaki Vulcan S पर 60 हजार रुपये तक वाउचर ऑफर किया गया है। इस बाइक पर यह अधिकतम छूट प्रदान की जा रही है। बता दें, 31 जनवरी 2023 तक ही वैध रहेंगे या फिर स्टॉक खत्म होने तक इन्हें जारी रखा जाएगा।

Kawasaki Ninja 650 बाइक लेने वालों के लिए भी शानदार मौका है, क्योंकि इस पर भी 30 हजार रुपये तक की अधिकतम बचत की जा सकती है। इसके अलावा Versys 650 और Ninja 400 पर भी ये ऑफर सीमित समय के लिए रहने वाला है। Versys 650 के लिए ये 20 हजार रुपये और Ninja 400 के लिए 40 हजार रुपये तक जाता है।

डीलरशिप से लें जानकारी

अगर आप कंपनी के द्वारा दिए गए इन ऑफर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कावासाकी डीलरशिप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। बता दें हाल ही में ब्रांड की तरफ से एलिमिनेटर 500 (Eliminator 500) को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 5.62 लाख रुपये एक्सशोरूम से शुरू होती है। कावासाकी डीलरशिप पर इस बाइक के लिए बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेटेस्ट लॉन्च बाइक में

451cc का पेरलल लिक्विड कूल्ड इंजन प्रदान किया जाता है। इस इंजन को 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसमें असिस्ट और स्लिप क्लच का भी ऑप्शन मिलता है।



ग्राहकों को झटका! होण्डा एलीवेट की कीमतों में हुआ इजाफा, चेक करें नई प्राइस

होंडा एलिवेट के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस बेस मॉडल की कीमत पहले 10.99 लाख रुपये एक्सशोरूम से शुरू होती थी लेकिन अब इसमें 58 हजार रुपये की वृद्धि हुई है। जिसके बाद नई कीमत 11.57 लाख रुपये हो गई है। जबकि अन्य वेरिएंट 20 हजार रुपये मंहगे हो गए हैं। यहां इसी के बारे में जान रहे हैं।

नई दिल्ली। होंडा के द्वारा होंडा एलिवेट को मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में पिछले वर्ष सितंबर महीने में पेश किया गया था, यह गाड़ी बिक्री के मामले में तगड़ा रतबा जमाने में कामयाब रही थी, हालांकि अब होंडा ने ग्राहकों को एक तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने होंडा एलिवेट के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है। यहां इस गाड़ी की नई कीमतों के बारे में बताने वाले हैं।

होंडा एलिवेट के सभी वेरिएंट्स की कीमत

Honda Elevate के SV MT वेरिएंट की कीमत पहले 10.99 लाख रुपये एक्सशोरूम से शुरू होती थी लेकिन अब इसमें 58 हजार रुपये की वृद्धि हुई है। जिसके बाद नई कीमत 11.57 लाख रुपये हो गई है। बता दें, सबसे ज्यादा इसी वेरिएंट की कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि अन्य वेरिएंट्स की कीमतों में 20,000 हजार रुपये का इजाफा किया गया है। होंडा एलिवेट के टॉप वेरिएंट ZX CVT की कीमत अब 16.19 लाख रुपये हो गई है।

ग्राहकों को खूब पसंद आई गाड़ी

होंडा एलिवेट की इस गाड़ी को ग्राहकों ने जमकर प्यार दिया है, इस गाड़ी ने पहले 100 दिनों में 20 हजार युनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार किया था और नवंबर 2023 कंपनी की बेस्ट सेलिंग गाड़ियों में भी शामिल रही थी।

Honda Elevate के फीचर्स और इंजन

इस गाड़ी में 1498cc की क्षमता वाला 4 सिलेंडर इंजन प्रदान किया जाता है, जो 119.35 बीएचपी की अधिकतम शक्ति और 145 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। गाड़ी में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है। सामान रखने के लिहाज से इसमें 458 लीटर का बूस्ट स्पेस मिलता है।

अन्य फीचर्स के रूप में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एयरबैग, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और अलॉय व्हील दिए जाते हैं।

शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है ये ऑफ रोडिंग कारें, कीमत 10 लाख से शुरू

ऑफ रोडिंग कार को चलाने में काफी अच्छा लगता है। इनकी राइडिंग एक्सपीरियंस काफी अलग ही होती है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। हमारी लिस्ट में ऑफ रोडिंग के लिए इसुजु वी-क्रॉस है। ये एक शानदार एसयूवी है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 225 मिमी है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 22.07 लाख रुपये से लेकर 27 लाख रुपये तक जाती है।

नई दिल्ली। क्या आप अपने लिए एक नई ऑफ रोडिंग कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी शानदार लुक के साथ आने वाली तो आज हम आपके लिए भारतीय बाजार में मौजूद ऑफ रोडिंग कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। ऑफ रोडिंग कार को चलाने में काफी अच्छा लगता है। इनका राइडिंग एक्सपीरियंस काफी अलग ही होता है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं।

Citroen C5 Aircross SUV

भारतीय बाजार में सिट्रोएन सी5 एयरक्रॉस एसयूवी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 230 मिमी का है। मार्केट में इस कार की कीमत 37.17 लाख रुपये एक्स शोरूम है।

Mahindra Thar

मार्केट में ये कार ऑफ रोडिंग के लिए ही जानी जाती है। थार आज से ही नहीं ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है। ये कई समय से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इस कार की ग्राउंड क्लीयरेंस 226 मिमी है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 10.54 लाख रुपये से शुरू है जो 16.78 लाख रुपये तक जाती है।

Isuzu V-Cross

हमारी लिस्ट में ऑफ रोडिंग के लिए

इसकी कीमत 5.62 लाख रुपये एक्सशोरूम से शुरू होती है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 225 मिमी है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 22.07 लाख रुपये से लेकर 27 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।

Toyota Fortuner

टोयोटा फॉर्च्युनर भारतीय बाजार में लोगों की फेवरेट एसयूवी में से एक है। इस कार में 220 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 32.99 लाख रुपये से शुरू होती है जो 50.74 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।

Honda elevate

भारतीय बाजार में ये कार इसी साल लॉन्च हुई है। आते ही इस कार की डिमांड मार्केट में काफी तेजी से बढ़ गई। इस कार की ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिमी है। इस कार की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 16 लाख रुपये तक जाती है।



पीएम पद और सीट शेयरिंग बड़ी बाधा



योगेंद्र योगी

इंडिया गठबंधन की चार बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर कोई नतीजा नहीं निकलने से साफ संकेत हैं कि यह मुद्दा बोटल के जिन्न की तरह है, दलों की एकता भंग हो सकती है



मुताबिक अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतेगा। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि 80 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। सपा अध्यक्ष के बयान से जाहिर है कि उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। अर्थात कांग्रेस को अखिलेश यादव ने उत्तरप्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। लेकिन यह निश्चित है कि अखिलेश यादव आसानी से कांग्रेस से सीट शेयरिंग करने को तैयार नहीं होंगे। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती कि बैठक में कोई ठोस निर्णय से पहले किसी तरह की जल्दबाजी करे। ऐसे में विपक्ष की एकता के बिखराव का ठीकरा कांग्रेस के सिर फूटेगा। इसी से कांग्रेस फिलहाल बचना चाहती है। सीट शेयरिंग का मुद्दा इंडिया गठबंधन के लिए सुलझाना आसान नहीं है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन देशभर में बीजेपी से मुकाबला करेगा। बंगाल में इस लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी। इससे जाहिर है कि ममता ने कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया है कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का मुगालता नहीं पाले। इस पर भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कांग्रेस के बिहार में भी सीट शेयरिंग के दरवाजे आसानी से खुलने की संभावना नहीं है। ममता और अखिलेश की तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को समर्थक रहे हैं कि जिन राज्यों में जिन दलों का

प्रभाव है, अर्थात पिछले लोकसभा चुनाव में जिस दल की सीटें जितनी हैं, उस हिसाब से सीट शेयरिंग की जाए। ऐसे में बिहार में कांग्रेस के लिए तालमेल बिठाना मुश्किल है। कमोबेश यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप की है। केजरीवाल भी कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब से बाहर रखना चाहते हैं। केजरीवाल की पार्टी के अन्य नेता इस बात के संकेत दे चुके हैं, यदि समझौता हुआ भी तो कांग्रेस के हिस्से में नाममात्र को सीटें ही आएंगी। सीट शेयरिंग की तरह ही प्रधानमंत्री पद का मुद्दा भी विपक्ष की एकता की कवायद को आगे बढ़ाने में मुश्किल पैदा कर रहा है। हालांकि यह मुद्दा तुलनात्मक रूप से फिलहाल इतना बड़ा नहीं है। दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने पर यह मुद्दा गरमा गया। हालांकि खड्गे ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने से इंकार कर दिया। खड्गे ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखने की इच्छा व्यक्त की थी और इस बात पर जोर दिया था कि इंडिया गठबंधन को पहले पर्याप्त संख्या में लोकसभा सीटें जीतने की जरूरत है। ममता और केजरीवाल के बीच इस बात के कयास लगाए गए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड्गे का नाम आगे बढ़ाए जाने से नाराज हैं। नीतीश कुमार ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का सुझाव और उन्हें गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने के कारण उन्हें मायूसी हुई और इसको लेकर उन्हें नाराजगी है। इंडिया गठबंधन के गठबंधन के लिए खड्गे को लक्ष्य के रूप में नहीं माना जा रहा है। खड्गे ने प्रधानमंत्री पद के लिए बला चुके हैं। इंडिया गठबंधन की चार बड़ी बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर कोई नतीजा नहीं निकलने से इस बात के साफ संकेत हैं कि यह मुद्दा बोटल के जिन्न की तरह है, जिसके निकलने के सामने नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन चार महत्वपूर्ण जातीय वर्गों की घोषणा की थी, किसान उनमें एक हैं। भारत सरकार के विज्ञापन आजकल

कृषि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकार की खरीद नीति का विश्लेषण जरूरी हो गया है, क्योंकि इन दोनों से, एक हद तक, कुछ खास फसलों को ही फायदा है। ये नीतियां बाजार में विकृतियां पैदा कर रही हैं। तेल के बीज और दालों के किसानों को दो स्टोर पर नीतिगत भेदभाव झेलना पड़ रहा है। उनके एमएसपी कागजों पर ही लिखे हैं, जबकि धान, गेहूं और गन्ने के साथ ऐसा नहीं है। इन फसलों को या तो सरकार प्रत्यक्ष तौर पर खरीदती है अथवा गन्ने के लिए चीनी मिलों को भुगतान करने को बाध्य करती है। राजस्थान में सरसों करीब 5000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बेचा जा रहा है और महाराष्ट्र में चने के दाम 4700 रुपए प्रति क्विंटल हैं। नीतिगत भेदभाव यह है कि सरसों का एमएसपी 5650 रुपए और चने का 5440 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों के लिए गारंटी शुद्धा एमएसपी और फसलों के घोषित मूल्य पर उनकी खरीद के दोनों मुद्दे अनंत और प्राचीन लगते हैं, क्योंकि बीते 50 साल में किसी भी सरकार ने इनके नीतिगत समाधान की सार्थक कोशिश नहीं की है। मौजूदा सरकार से आर्म अपेक्षा इस लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव मात्र तीन माह दूर ही है। किसान आंदोलन मूल्य वषा विमर्श किया और किस बिंदु तक पहुंची है, इसका कोई भी खुलासा देश के सामने नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन चार महत्वपूर्ण जातीय वर्गों की घोषणा की थी, किसान उनमें एक हैं। भारत सरकार के विज्ञापन आजकल

संपादक की कलम से एमएसपी गारंटी दे सरकार



एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकार की खरीद नीति का विश्लेषण जरूरी हो गया है, क्योंकि इन दोनों से, एक हद तक, कुछ खास फसलों को ही फायदा है। ये नीतियां बाजार में विकृतियां पैदा कर रही हैं। तेल के बीज और दालों के किसानों को दो स्टोर पर नीतिगत भेदभाव झेलना पड़ रहा है। उनके एमएसपी कागजों पर ही लिखे हैं, जबकि धान, गेहूं और गन्ने के साथ ऐसा नहीं है। इन फसलों को या तो सरकार प्रत्यक्ष तौर पर खरीदती है अथवा गन्ने के लिए चीनी मिलों को भुगतान करने को बाध्य करती है। राजस्थान में सरसों करीब 5000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बेचा जा रहा है और महाराष्ट्र में चने के दाम 4700 रुपए प्रति क्विंटल हैं। नीतिगत भेदभाव यह है कि सरसों का एमएसपी 5650 रुपए और चने का 5440 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों के लिए गारंटी शुद्धा एमएसपी और फसलों के घोषित मूल्य पर उनकी खरीद के दोनों मुद्दे अनंत और प्राचीन लगते हैं, क्योंकि बीते 50 साल में किसी भी सरकार ने इनके नीतिगत समाधान की सार्थक कोशिश नहीं की है। मौजूदा सरकार से आर्म अपेक्षा इस लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव मात्र तीन माह दूर ही है। किसान आंदोलन मूल्य वषा विमर्श किया और किस बिंदु तक पहुंची है, इसका कोई भी खुलासा देश के सामने नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन चार महत्वपूर्ण जातीय वर्गों की घोषणा की थी, किसान उनमें एक हैं। भारत सरकार के विज्ञापन आजकल

खुब प्रसारित कराए जा रहे हैं कि कितने करोड़ किसानों को 'सम्मान राशि' के तौर पर कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। जिन फसलों का आज हम उल्लेख कर रहे हैं, वे खेतों में हैं और दो माह की अवधि में ही उन्हें बाजार में बेचना अनिवार्य है। दूसरा बिंदु आयात का है। गेहूं, मिलों के चावल और चीनी की आयात-दरें बहुत ज्यादा हैं। सोयाबीन और सूरजमुखी सरीखे खाद्य-तेलों की आयात-दर शून्य है। ऐसा ही अधिकतर दालों के संदर्भ में है। गेहूं और धान के उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। चीनी उत्पादन में भी हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। यदि सरकार फसलों के एमएसपी को कानूनन सुनिश्चित करा दे और एमएसपी पर खरीद के दायरे में अधिक किसान और 23 से अधिक फसलें लाई जाएं, तो किसानों की आमदनी का मुद्दा बहुत हद तक हल किया जा सकता है। किसान इतना कर्जदार भी नहीं रहेगा। अब भी किसान पर औसतन कर्ज करीब 75,000 रुपए का है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें कर्ज माफ़ी के दावे करती रही हैं। बहरहाल कृषि का इतना परिदृश्य जरूर बदला है कि दालों का आयात काफी कम हुआ है, लेकिन खाद्य-तेलों का आयात बढ़ाना पड़ा है। चूंकि मोदी सरकार ने फसल उत्पादक समर्थक से उपभोक्ता समर्थक की नीति बदली है, नीतिगत आयात फिर बढ़ता दिख रहा है। विभिन्न सरकारी विभाग एमएसपी और खरीद नीति को लेकर अपनी चिंताएं और सरोकार जताते रहते हैं, लेकिन यह वाकई आश्चर्यजनक है कि एमएसपी आज तक तथ्यों नहीं किया जा सका।

चर्चा हिमाचली फरियाद का दर्द

हिमाचल के वित्तीय हालात प्रदेश को फरियादी बना चुके हैं या हमने अपने अर्थतंत्र के तमाम सबूतों को केंद्र के पास गिरवी रख दिया। भले ही डबल इंजन सरकार के पहरावे में पूर्व सरकार के पांच साल निकल गए या अब व्यवस्था परिवर्तन की राह पर कांग्रेस सरकार की जद्दोजहद सामने आ गई, लेकिन पर्वतीय प्रदेश का वजूद अब केंद्र का खिलौना बना नXR आ रहा है। केवल एक बार धूमल सरकार के वक्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हिमाचल को लगे लगाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, अन्यथा ढोल-ढमाकों ने सिर्फ सियासी घोंसलों में सपने ही दिए। प्रदेश के कले में लटका अस्सी हजार करोड़ का ऋण, वित्तीय संसाधनों की कमी और ऊपर से प्राकृतिक आपदा से रूबरू होने का दर्द अब दरबारी बनकर दिल्ली सरकार के समक्ष धूम रहा है। एक साल की कसरतों ने कितने भी ढोए आंसु, मगर सियासत का रंगिस्तान इन्हीं का प्यासा रहा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात के जगह और केंद्रीय राहत के पन्ने दर्द से भर हैं, लेकिन इंतजार है उस घड़ी का जब बरसात की त्रासदी को केंद्र से राहत का पैगाम मिले। आपदा के बाद जरूरतों का मूल्यांकन 9727 करोड़ की आशा में केंद्र को टुकर-टुकर पुकार रहा है और यही दरखास्त लिए मुख्यमंत्री देश से अपने हक की फरियाद करते हैं। यह दौर है कि प्रदेश में अपने स्तर पर राहत पैकेज के तहत 4500 करोड़ की राशि तय की और हर प्राविगत के मत में दस्तक दी। हिमाचल की यह वही जनता है जिसके सामने प्रधानमंत्री स्वयं रोड शो करते हुए आशवासन की मुद्रा में केंद्र की गारंटी बने नXR आते थे। एक साल पहले हिमाचल के साथ केंद्र के रिश्ते अब क्यों सियासी पाला बदल कर बहरे हो गए या यही की पूरी जनता दोषी हो गई। क्या प्राकृतिक त्रासदी में भी सियासी विरोध के सुर सुने जाने चाहिए या यह मान लिया जाए कि अगले कुछ साल यह प्रदेश सियासी नरक के जखम इसलिए ढोएगा क्योंकि केंद्र में दूसरी पार्टी का बादशहा बैठा है।

वोट के बीच मतांतर देखने की दूरबीन अगर यूं ही निरीह व रूढ़ी रही तो यह मानना पड़ेगा कि हिमाचल को वित्तीय संकट में फंसाने के लिए केंद्र सरकार भी बहाने बना रही है। वित्तीय प्रबंधन की अति कठिन परीक्षा में सुक्खू सरकार के लिए केंद्र सरकार का रवैया फिलहाल मुकद्द नहीं है। अड़चनों की फैहरिस्त में राज्य की मजबूरियों को बढ़ाकर सतर लाख लोगों का अपमान करना अगर राजनीतिक सौगत है, तो हिमाचल के भाजपा विधायक व सांसद भी क्यों न जिम्मेदार समझे जाएं। इसी जनता ने कल अगर भाजपा को आसन दिया तो आज कांग्रेस को मिले बहुमत को मिल रही यह सजा, वास्तव में प्रदेश के जनोदेश का ही विरोध है। केंद्र गारंटी बनाम गारंटी, जीएसटी बनाम जीएसटी, योजना बनाम योजना और परियोजना बनाम परियोजना चुनने लगा तो हिमाचली इच्छाओं, संभावनाओं, विकास और दायित्व का वित्तीय पोषण ईमानदारी से नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के हर तंत्र और विकास के हर रास्ते को केंद्र सरकार का शूष संदेश चाहिए वरना इन हालात में सिर्फ छोटकशी मिलेगी। हिमाचल में बाहरी संसाधनों से विकास के रास्तों पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। वित्तीय पोषण के बाहरी स्रोतों से पहले ही चौदह हजार करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसी रास्ते से वर्तमान सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी व पूरे प्रदेश के टूरिज्म डिवेलपमेंट पर 2800 करोड़ की योजना को अमलीजामा पहनाना चाहती है, लेकिन शर्तों की कठिनाई में अगले कुछ सालों तक धन उपलब्ध नहीं होगा।

राजेंद्र ठाकुर

हिमाचल को क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी टूरिज्म चाहिए। संस्कृति का संरक्षण हो।

25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना हिमाचल एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। यहां के ऐतिहासिक मंदिरों और प्राचीन ग्रंथों में मिले उल्लेख के कारण इस हिमालयी क्षेत्र को पूर्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता था। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डा. वाईएस परमार की प्रदेश के निर्माण में अब भूमिका रही है, इसलिए उन्हें हिमाचल निर्माता के रूप में जाना जाता है। हिमाचल में आय के संसाधन नाममात्र थे, लोग गरीब थे और जीवनन्यापन के लिए कृषि पर निर्भर थे। इसलिए वाईएस परमार ने हिमाचलियों के हितों की रक्षा के लिए 1972 में विशेष कानून बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे राज्यों के धनी लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदने से रोकना था। इसके लिए हिमाचल प्रदेश टेनसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 के लिए 1976 में नियम बनाए गए थे। परंतु समय के साथ धारा 118 का स्वरूप बिगड़ता चला गया और पर्यटन विकास के नाम पर बाहरी लोगों के बड़े-बड़े होटल बनते चले गए। इसी कड़ी में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की सी हेक्वेयर भूमि टूरिज्म विलेज बनाने के लिए सरकार को हस्तांतरित करने के सरकारी आदेश के पीछे का मकसद क्या है और सलाहकार कौन है, यह सवाल सरकार की संपूर्ण कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा करता है।

यह टूरिज्म विलेज कौन बनाएगा, क्या

एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भूमि पर सरकार कब्जा कर किसी निजी व्यक्ति, इंस्टीट्यूट या कारपोरेट को सौंपना चाहती है? विदेशी संस्कृति की तज पर बनने वाले टूरिज्म विलेज में कैसिनो, पब, जुआ- सब होंगे, तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फैकल्टी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसे अत्याधुनिक टूरिस्ट सेंटर से क्या प्रदेश की संस्कृति और युवा नशे की चपेट में आने से बच पाएंगे? स्थानीय लोग और कई समाजसेवी संस्थाएं सुक्खू सरकार के इस आदेश के विरोध में एकजुट हो चुके हैं और आने वाले दिनों में यह विरोध बढ़ता जाएगा। जरूरत तो कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सरकारी की सार्थक भूमिका की थी, परंतु पैसें की चकाचौध में सरकार को इस क्षेत्र में ऐसे नकारात्मक फैसले लेने की सलाह कौन और क्यों दे रहा है, यह सवाल आज हर प्रदेशवासी के दिलों-दिमाग पर हाई है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्मीदों के साथ सरकार को अपना बेशकीमती वोट देकर चुना था। अभी तक तो सरकार चुनावों में किए वादे भी पूरे नहीं कर पाई है। कहीं क्या न हो कि सुक्खू सरकार के ऐसे लोक अहितकारी फैसले जल्द होने जा रहे आम चुनावों में अपना रंग दिखा जाएं, इसलिए ऐसे फैसले लेने से पहले सरकार को जरूर सोचना चाहिए। पर्यटन के विकास के साथ-साथ प्रदेश की संस्कृति को सहेजना भी सरकार का कर्त्तव्य है। अत्याधुनिक टूरिज्म विलेज के स्थान पर हैरिटेज विलेज की स्थापना होनी चाहिए, वो भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जगह पर

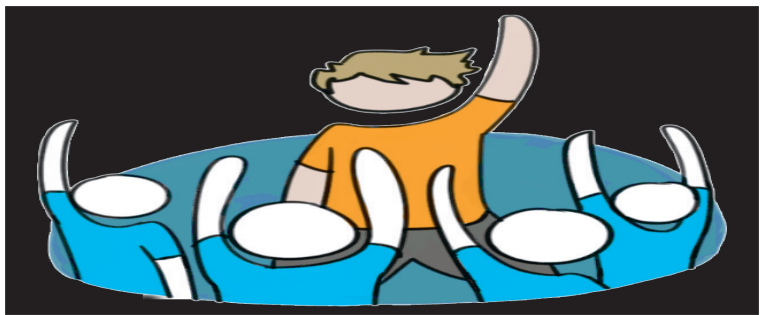


नहीं, बल्कि शहर से दूर किसी खाली पड़ी पहाड़ी पर, जहां हिमाचल की संस्कृति, खानपान, आर्किटेक्चर, लोकगीत व पहरावे से पर्यटकों को स्मरण करवाया जा सके। हिमाचल को नशे और जुए का अड्डा बनने से रोकने के लिए विरोध किसी भी हद तक जा सकता है।

यह सच है कि राज्य की सरकारों के पास आय का कोई विशेष स्रोत नहीं होने के कारण प्रत्येक सरकार ने औद्योगीकरण और पर्यटन को बढ़ावा दिया। हालांकि पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम हिमाचल में पर्यावरण विरोधी उद्योगों के हमेशा खिलाफ रहे तथा प्रदेश के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली ईको-फ्रेंडली इंडस्ट्री की हिमायत करते रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बीरभद्र सिंह भी प्रदेश के पर्यावरण से छड़छाड़ के विरोधी रहे तथा उनके कार्यकाल में भी ऐसा कोई बड़ा उद्योग

वाले नेताजी इंडी की पावर को चुनौती दे रहे हैं। यह इंडी की पावर है कि उसने जिस जिस को समन भेज कर बुलाया है, उसे सीधा अंदर टोक दिया है। इंडी के हाथ बड़े लंबे हैं। उसकी तुलना मैं न चाहते हुए भी अपनी पत्नी से कर सकता हूं। उसके हाथ भी बहुत लंबे हैं। इंडी और सीबीआई की तरह मेरी पत्नी की महिमा भी अपरंपार है। मेरी कोई भी हरकत उससे छिपी हुई नहीं है। गाहे बगाहे मुझे आत्मसमर्पण की मुद्रा में खड़ी कर देती है। मैं उसे इंडी और सीबीआई के नाम पर डरा भी नहीं सकता।

मैं उसे गच्चा देने के लिए ध्यान भी नहीं लगा सकता। उसका ध्यान मेरे पर नहीं है, उसे मेरा ध्यान भंग हो जाता है। जैसे मेनका ने ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया था। विश्वामित्र को लेकर मेरे मन में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन मेरी पत्नी के मन में इंडी और सीबीआई को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं दुविधा में हूं काके लागू पाए खैर। मैं अपने दिल को समझा रहा हूं कि हर पत्नी इंडी और सीबीआई की तरह होती है उससे बहुत



डिप्लोमेटिक तरीके से पेश आना चाहिए। दोनों का मुस्कुरा कर स्वागत करना चाहिए। मुस्कुराने से कई समस्याएं हल हो जाती हैं। यह एक्सपीरियंस मुझे कॉलेज के दिनों में हुआ था जब किसी ने मुस्कुरा कर मुझे हेलो कहा था और मैं उसका हो लिया था। जिसका तब मैं हो लिया था, उसकी निगाहें कभी सीबीआई और इंडी की तरह परम रडार युक्त हो सकती हैं, यह मैंने तब सीखा था। लेकिन अब सोचने का क्या फायदा। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया

चुग गई खेत। बुजुर्गों ने कहा है कि जब मुसीबत आन पड़े तो ध्यान लगाइए। कोई कुर्सी पर बैठा बैठा ईश्वर का ध्यान लगा रहा हो तो कोई बिस्तर पर लेटा लेटा ध्यान लगा रहा है। कोई ध्यान लगाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए किसी तपोवन में चला गया है। कुर्सी और बिस्तर पर तो सीबीआई और इंडी कभी भी धमक सकती है, लेकिन तपोवन का ताप इतना प्रभावी होता है कि वहां ध्यान लगा रहे व्यक्ति पर इंडी और सीबीआई की पावर नहीं चलती।

वहां सिर्फ ध्यान की शक्ति चलती है। इसलिए नेताजी ध्यान लगा कर बैठ गए हैं और सीबीआई उस तपोवन के बाहर अपने आकाओं के निर्देश का इंतजार करने बैठ गई है। अब नेताजी किस बात का ध्यान लगा रहे हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है। लोग महंगाई की चपत भूल गए हैं। भ्रष्टाचार के थपड़े भूल गए हैं। राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र भूल गए हैं। बेरोजगारी भूल गए हैं। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेताजी के ध्यान पर है। पब्लिक को उम्मीद है कि नेताजी ध्यान से हटेंगे तो उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई और इंडी जैसी सर्वशक्तिमान एजेंसियां इस ताक में बैठी हैं कि कब नेताजी का ध्यान भंग हो और कब उनकी पावर का जलवा शुरू हो। अब जंग ध्यान और पावर के बीच लग गई है। पब्लिक कंप्यूज है। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है कि वह नेताजी के ध्यान पर ध्यान लगाए या सीबीआई के नोटिस पर ध्यान लगाए। यही तो ध्यान की महिमा है और यह महिमा अपरंपार है।

गुरमीत बेदी

कड़कड़ाती टंड की वजह से कैंसिल हो गई आपकी फ्लाइट तो ट्रेवल इंशोरेन्स आएगा आपके काम, यहां जानें कैसे होगा मददगार

अक्सर टंडी के समय हमारी ट्रेन और प्लाइट्स कैंसिल हो जाती है क्योंकि मौसम की खराबी के कारण इसको चलाने आसान नहीं होता है। ऐसे स्थिति में अगर आपने ट्रेवल इश्योरेंस लिया है तो वह आपके लिए मददगार हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि प्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में कैसे इश्योरेंस आपके काम आएगा। आइये इसके बारे में विस्चार से जानते हैं।

नई दिल्ली। ये कोई नई बात नहीं है कि ज्यादा कोहरे और मौसम की खराबी के कारण फ्लाइट्स या ट्रेन कैंसिल हो गई हो। लगभग हर साल हम ऐसा होता है, जब ज्यादा ठंड के कारण ऐसा होता है। मगर ऐसा होने पर हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। इस स्थिति में ट्रेवल इश्योरेंस हमारे बहुत काम आ सकता है, ताकि कम से कम आपको कोई फाइनेंशियल हानि ना पहुंचे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी प्लाइट कैंसिल हो जाती है तो कैसे आप इश्योरेंस की मदद ले सकते हैं। कोहरे के कारण प्लाइट होती है कैंसिल जैसा कि हम जानते हैं कि घने कोहरे के कारण हाल ही में भारत के कई शहरों में प्लाइट के रद्द होने से कई यात्री फंसे हुए हैं , जिस कारण उनकी सारी प्लानिंग खराब हो गई हैं।



इसलिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर एयरलाइंस से कैंसिलेशन में बढ़ोतरी से लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए उनका ध्यान रखने की गुजारिश की है। बता दें कि प्लाइट कैंसिल होने या इसमें देरी होने पर लोगों को इसका रिफंड

मिलता है, मगर यदि आपके पास ट्रेवल इश्योरेंस है तो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। आइये जानते हैं आपके बीमा में क्या-क्या कवर होता है। **ट्रिप कैंसिल होने की स्थिति** मान लीजिए कि आप कही जा रहे हैं और वहां प्राकृतिक आपदा, आग लगने, तूफान

आने के कारण आपको अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा आपके होटल, फ्लाइट और अन्य खर्चों को मैनेज किया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। ये लिमिट आपके बीमा राशि के हिसाब से होगा।

ऐसे ही अगर कोहरे या ज्यादा बारिश की स्थिति में आपकी प्लाइट कैंसिल होती है और एयरलाइन आपको कोई रिफंड नहीं दे रही है तो बीमा कंपनी आपको टिकट के पैसे रिफंड करेगी। **फ्लाइट लेट होने की स्थिति** अगर खराब मौसम के कारण आपके प्लाइट कुछ समय की देरी से उड़ान भरने वाली है तो इस स्थिति में भी आपके इश्योरेंस आपके काम आ सकता है। इस स्थिति में बीमा कंपनी इस पूरे समय में आपके खर्चों और जरूरतों का ध्यान रखते हुए इसके लिए आपको भुगतान करेगी। कनेक्टिंग प्लाइट मिल होने की स्थिति अगर आप कहीं कनेक्टिंग फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं और एयरलाइन की गलती के कारण आपकी कनेक्टिंग प्लाइट छूट जाती है तो ऐसे स्थिति में भी आपका बीमा आपके काम आता है। एयरलाइन द्वारा की गई देरी के कारण पहले से बुक की गई आगे की कनेक्शन फ्लाइट छूटने पर आपको अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी, अगर एयरलाइन इसके लिए कोई उपाय नहीं करती है तो। कंपनी आपके फ्लाइट टिकट, होटल और ट्रेवल एक्सपेंस का पूरा ध्यान रखेगी और आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे।

सरकार से वित्तीय सहायता के लिए आग्रह कर रहा टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, यहां जानें डिटेल

कपड़ा मिल संघों ने गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दों के साथ-साथ एक्सपोर्ट में मंदी के कारण चल रहे संकट से निपटने में मदद के लिए सरकार से वित्तीय राहत की मांग की है। शुक्रवार को एक अपील में कपड़ा मिल संघों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा कि निर्यात में मंदी के कारण उद्योग तीव्र वित्तीय तनाव से गुजर रहा है। मुंबई। कपड़ा मिल संघों ने गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दों के साथ-साथ एक्सपोर्ट में मंदी के कारण चल रहे संकट से निपटने में मदद के लिए सरकार से वित्तीय राहत की मांग की है। शुक्रवार को एक अपील में कपड़ा मिल संघों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा कि निर्यात में मंदी के कारण उद्योग तीव्र वित्तीय तनाव से गुजर रहा है। लंबे समय तक यूक्रेन जैसे बाहरी कारकों के बाद विशेष रूप से कपास आधारित खंड में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। वैश्विक संघर्षों के लंबे समय तक आर्थिक प्रभाव, कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क और मानव निर्मित फाइबर (MMF) गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से संबंधित मुद्दों जैसी चुनौतियों के कारण क्षमता उपयोग में 50 प्रतिशत से लेकर महत्वपूर्ण गिरावट आई है। बयान में

कहा गया है कि लगभग एक साल तक यह 70 फीसदी तक पहुंच गया। इसमें कहा गया है कि इस स्थिति ने कई कताई मिलों, विशेष रूप से SMEs को गंभीर वित्तीय तनाव में धकेल दिया है, जिससे वे ऋण चुकाने और स्थायी शुल्क पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। **वित्तमंत्री से किया आग्रह** इन चुनौतियों में कपड़ा मिल एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि वे बैंकिंग क्षेत्र को एक विशेष मामले के रूप में उद्योग के लिए वित्तीय सहायता उपायों का विस्तार करने की सलाह दें, और मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए एक साल की मोहलत दी जाएं और तीन साल कर दिया जाएं। ECLGS के तहत वार्षिक लोन को छह-वर्षीय अवधि के लोन में बदलना और कार्यशील पूंजी पर तनाव को कम करने के लिए मामले-दर-मामले आधार पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने की पंग की। भारतीय कपड़ा उद्योग परिषद (CITI) के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि हम वित्त मंत्री से अपील करते हैं कि कताई क्षेत्र में आए अप्रत्याशित संकट को कम करने, कई लाख लोगों की नौकरी जाने से रोकने, बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमारी दलीलों पर अनुकूलता से विचार करें।

1 मार्च से बीटूबी ई-इनवॉयस विवरण के बिना नहीं बनेगा ई-वे बिल, इन व्यवसायों के लिए बदलेगा नियम



राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने कहा कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ करदाता जो ई-चालान के लिए पात्र हैं B2B (बिजनेस टू बिजनेस) और B2E (बिजनेस टू एक्सपोर्ट) के लिए E-इनवॉयस से लिंक किए बिना ई-वे बिल तैयार कर रहे हैं। 1 मार्च से नए नियम के अनुसार 5 करोड़ से अधिक वाले व्यवसायों को B2B लेनदेन के लिए ई-इनवॉयस के बिना ई-वे बिल नहीं मिलेगा।

नई दिल्ली। पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले व्यवसाय एक मार्च से सभी B2B लेनदेन के लिए ई-चालान विवरण शामिल

किंग बिना ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे। बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत, 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर-राज्य परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने कहा कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ करदाता, जो ई-चालान के लिए पात्र हैं, B2B (बिजनेस टू बिजनेस) और B2E (बिजनेस टू एक्सपोर्ट) के लिए E-इनवॉयस से लिंक किए बिना ई-वे बिल तैयार कर रहे हैं। इनमें से कुछ मामलों में, ई-वे बिल और e-इनवॉयस के तहत अलग-अलग दर्ज किए गए चालान विवरण कुछ मापदंडों के संबंध में

मेल नहीं खा रहे हैं। इससे ई-वे बिल और ई-इनवॉयस स्टेटमेंट में बेमेल का मामला सामने आ रहा है। **1 मार्च से होगा बदलाव** ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, एनआईसी ने जीएसटी करदाताओं को सूचित करते हुए बताया कि 1 मार्च 2024 से ई-इनवॉयस विवरण के बिना ई-वे बिल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह ई-इनवॉयस सक्षम करदाताओं और B2B और एक्सपोर्ट के तहत आपूर्ति से संबंधित लेनदेन के लिए लागू है। हालांकि, एनआईसी ने कहा कि B2C और गैर-आपूर्ति जैसे अन्य लेनदेन के लिए ई-वे बिल बिना किसी बदलाव के सामान्य रूप से काम करेंगे।

अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के दायरे में लाए जाएंगे और ज्यादा उत्पाद-पीयूष गोयल

परिवहन विशेष न्यूज

उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा गुणवत्ता मानकों के पालन से भारत को विकसित राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी। गोयल ने यह भी कहा कि इसके लिए बीआईएस को गुणवत्ता मानकों का एंवेसडर बनना चाहिए। इसे सिर्फ मानकों को अपनाने वाला नहीं बनना चाहिए बल्कि मानकों का अग्रणी बनना चाहिए। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि सरकार और अधिक उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के दायरे में लाएगी। इसका कारण यह है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 77वें स्थापना दिवस को वचुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्पादों और सेवाओं में उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करने से भारत को उच्च लक्ष्य हासिल करने और एक विकसित राष्ट्र बनने में मदद मिलेगी।

BIS को गुणवत्ता मानकों का होना चाहिए एंवेसडर गोयल ने यह भी कहा कि इसके लिए बीआईएस को गुणवत्ता मानकों का एंवेसडर बनना चाहिए। इसे सिर्फ मानकों को अपनाने वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि मानकों का अग्रणी बनना चाहिए। इसके अलावा, जहां भी संभव हो अंतरराष्ट्रीय मानकों के तुलनीय गुणवत्ता मानक तैयार करने चाहिए।

उन्होंने गुणवत्ता मानक बनाने के लिए अधिक से अधिक हितधारकों की भागीदारी का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के माध्यम से जारी गुणवत्ता मानकों के अनिवार्य

अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के दायरे में लाए जाएंगे और ज्यादा उत्पाद



अनुपालन के तहत अधिक उत्पादों को लाने से उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। अब तक 672 उत्पादों को कवर करते हुए 156 क्यूसीओ जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 14 क्यूसीओ के अंतर्गत केवल 106 उत्पाद शामिल थे। भविष्य में 2,000-2,500 उत्पादों को क्यूसीओ के दायरे में लाया जाएगा। गोयल ने कहा कि हाल के वर्षों में उठाए गए कदमों में सोने के आभूषणों की हालतमार्किंग और खिलौनों में अनिवार्य गुणवत्ता पालन प्रमुख हैं और इससे देश में बदलाव आया है।

विदेशी मानकों पर नहीं करेंगे काम मंत्री ने आगे कहा कि दशकों से भारत गुणवत्ता के लिए विदेशी मानकों पर निर्भर था। उन्होंने कहा कि अब, भारत की गति और प्रगति तय होगी और हमारे अपने मानकों पर निर्भर करेंगी। हम विदेशी मानकों पर नहीं, बल्कि अपने मानकों पर भरोसा करेंगे, इस प्रकार आत्मनिर्भर बनेंगे।

गोयल ने कहा कि हाल के वर्षों में की गई पहलों में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग

और खिलौनों में अनिवार्य गुणवत्ता अनुपालन प्रमुख हैं और इससे देश में बदलाव आया है।

एसबीआई वर्सेज पोस्ट ऑफिस टर्म्स डिपोजिट : किस एफडी में पैसा लगाना है ज्यादा फायदेमंद, यहां पढ़ें पूरी डिटेल



अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक सुरक्षित विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी बात ये है कि SBI और BOB जैसे कई बैंकों ने अपने पान दारों में बढ़ोतरी की है। आज हम आपको बताएंगे कि SBI की तीन साल वाली FD और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट रेट में से आपके लिए कौन सा बेहतर है।

नई दिल्ली। एक आम आदमी के लिए इन्वेस्ट करना एक बड़ा पहलू है। ऐसे में अक्सर हम ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खोजते हैं, जिसमें आपको ज्यादा फायदा मिले और डिपॉजिट रेट भी अच्छा हो। ऐसी स्थिति में FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एक सही विकल्प हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही बैंकों ने अपने टर्म डिपॉजिट रेट को बढ़ाया है। इसके साथ ही सरकार ने पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट पर इंस्ट्रेट रेट को बढ़ाया है। आइये जानें कि आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं।

बैंक की FD रेट में हुई बढ़ोतरी कुछ समय पहले ही ये सूचना आई है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ोदा (BoB), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बहुत से बैंकों ने हाल ही में टर्म डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी की है। वहीं 29 दिसंबर को केंद्र सरकार ने जनवरी-मार्च तिमाही के लिए तीन साल की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट (POTD) योजना पर ब्याज दरें बढ़ा दीं। आइए जानें कि तीन साल की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरों की तुलना

SBI की तीन साल की FD रेट से करें। **SBI और पोस्ट ऑफिस की FD रेट** बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने लगभग अपने सभी टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। यह दर 2 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर लागू की गई है। बता दें कि ये नई दर 27 दिसंबर 2023 से प्रभावी है। बैंक ने 3 साल से लेकर 5 साल से कम अवधि में मैच्यूर होने वाली एफडी पर दरों में 25bps की बढ़ोतरी की है। यानी की इन डिपॉजिट्स पर अब 6.75% ब्याज मिल रहा है। 3 साल से अधिक और 5 साल से कम समय वाली FD के लिए आपको पोस्ट ऑफिस 6.75% का ब्याज मिलेगा। सरकार ने 3-साल के डिपॉजिट पर ब्याज दर को 10 बेसिक प्वाइंट पर बढ़ाकर 7% से 7.10% कर दिया है। बता दें कि ये दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हैं। **SBI की लेटेस्ट FD रेट** अगर आप 7 दिन से 10 साल के बीच की SBI एफडी का चयन करते हैं तो बैंक आपको 3.5% से 7% तक चयन करेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को इन डिपॉजिट पर 50 बेसिक प्वाइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। **पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट रेट** पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट प्लान बैंक एफडी के समान ही हैं। मगर पोस्ट ऑफिस में आपको एक साल से लेकर पांच साल तक की टर्म डिपॉजिट की सुविधा देता है। फिलहाल सरकार ने जनवरी से मार्च तक इस दरों को अपडेट किया गया है। पोस्ट ऑफिस में एक साल की टर्म डिपॉजिट प्लान पर अब 6.9% और दो साल की अवधि के लिए 7% ब्याज मिलेगा।

बच्चे से हो गए बड़े पर नहीं बदली आधार पर फोटो? इन स्टेप्स को फॉलो कर मिन्टों में हो जाएगा काम

भारतीयों के लिए आधार कार्ड एक पहचान पत्र है जिसका इस्तेमाल आप सरकारी और गैर-सरकारी दोनों कामों के लिए कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समय-समय पर सरकार इसे अपडेट करने की सलाह देती रहती है। ऐसे में अगर आपने लंबे समय से अपनी फोटो को अपडेट नहीं किया है तो आप इसे बदल सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में 2010 में आधार कार्ड योजना शुरू हुई थी। आज के समय में आधार हमारे और आप के लिए कितना महत्व रखता है, ये तो हम सब अच्छे से जानते ही हैं। आधार हमारी पहचान है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव करना हो तो वह कैसे किया जाता है। वैसे तो इसमें कई प्रकार की जानकारी दी जाती है, जैसे फोटो, आपका एड्रेस, आपका ईमेल, फोन नंबर और बहुत कुछ। आज आपको हम बताने वाले हैं कि अपने आधार कार्ड की फोटो कैसे अपडेट कर सकते हैं। **आधार कार्ड पर बदल सकेंगे फोटो** अगर आपने अपने आधार कार्ड की फोटो लंबे समय से नहीं बदली है, तो इसपर विचार करने का

ये अच्छा टाइम है। UIDAI के मुताबिक 15 साल की उम्र के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी फोटो के साथ आधार की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य होता है। आधार कार्ड की फोटो में बदलाव के लिए अप्लाई करने के पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो जानकारी आपने आधार कार्ड बनवाने समय दी थी, जैसे नाम, पता, उम्र, जेंडर, फोन नंबर और ईमेल आईडी को भी ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। वहीं बायोमेट्रिक विवरण, जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए अपने पास के आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और न्यूनतम चार्ज देना होगा। **कैसे बदलें आधार की फोटो** यदि आप भी अपने आधार की फोटो अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको स्टैप बाइ स्टैप यहां सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट - uidai.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप आधार का नामांकन फॉर्म डाउनलोड करें (आप चाहें तो अपने पास के आधार सेवा केंद्र या आधार नामांकन केंद्र या फिर



पास के CSC केंद्र से भी इसका फॉर्म लेकर आ सकते हैं।) इसके बाद आप अपने आवश्यक जानकारी भरें। इसके बाद आप फॉर्म में भरी जानकारी को अपने पास के आधार सेवा केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर जमा करवा दें। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सबसे पास कौन सा आधार सेवा केंद्र है, तो आप इस इंटरनेट साइट (recruitments.uidai.gov.in/) पर जाकर भी पता लगा सकते हैं। जब आप केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो आपको वहां मौजूद कर्मचारी मिलगा, जो कि बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से सभी विवरणों की पुष्टि करेगा। इसके बाद वह कर्मचारी आधार कार्ड अपडेट करने

